RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 143 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » बुधवार » 17-12-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 बिरला ने सदस्यों से कहा : सदन 'ध्यान लगाने' का स्थान नहीं है

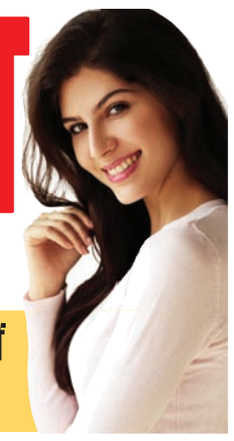

6 भाजपा में युवा नेतृत्व की नई आहट पर भरोसा

7 मैं एक ही फिल्म दो बार भी नहीं देखती : एलनाज नौरोजी

फर्स्ट टेक

छत्तीसगढ़ में 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

बीजापुर (छत्तीसगढ़)/भाषा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 26 पर सामूहिक रूप से 84 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) जितेंद्र यादव ने बताया कि सात महिलाओं सहित 34 नक्सलियों ने यहां वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि यह नक्सली माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना राज्य कमेटी और आंध्र ओडिशा सीमा डिवीजन में सक्रिय थे।

गोताखोरी में सहायक जहाज डीएससी ए20 नौसेना में शामिल

कोच्चि/भाषा। गोताखोरी में सहायक जहाज डीएससी ए20 को मंगलवार को नौसेना में शामिल किया गया। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना की गोताखोरी और जलीय क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस जहाज को कोच्चि नौसेना अड्डे पर एक समारोह में सेवा में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने की। यह इस साल सेवा में शामिल किया जाने वाला 11वां जहाज है, जो देश की जहाज निर्माण क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बॉण्डी बीच पर हुई गोलीबारी 'इस्लामिक स्टेट' से प्रेरित थी : ऑस्ट्रेलियाई पुलिस

मेलबर्न/एपी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉण्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान सरेआम गोलीबारी ''इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला'' था। ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस आयुक्त क्रिसी बैरेट ने मंगलवार को यह बात कही। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध हमलावर पिता और पुत्र थे। उन्होंने बताया है कि एक हमलावर (50) को पुलिस ने मार गिराया जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा घायल हो गया और अस्पताल में उसका उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो हमलावर मारा गया उसकी पहचान अधिकारियों ने साजिद अकरम के रूप में की है। मंगलवार को नेताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में अधिकारियों ने पहली बार संदिग्धों की विचारधाराओं के बारे में पुष्टि की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये टिप्पणियां प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित थीं, जिनमें 'जब्त किए गए वाहन में इस्लामिक स्टेट के झंडे मिलना' भी शामिल है।

विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरों को किया सलाम

भारतीय सशस्त्र बलों को गर्व और कृतज्ञता से नमन करता है राष्ट्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर वीरों को सलाम किया और कहा कि 1971 के युद्ध में निर्णायक जीत दिलाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को राष्ट्र गर्व और कृतज्ञता से नमन करता है।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह, नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सयान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी।

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में देश 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' के रूप में मनाता है।

रक्षा मंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, विजय दिवस पर, राष्ट्र 1971 की निर्णायक विजय दिलाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को गर्व और कृतज्ञता से नमन करता है। सेना, नौसेना और वायु सेना ने शानदार समन्वय के साथ कार्य किया, इतिहास को नया रूप दिया और भारत के रणनीतिक संकल्प को मजबूत किया। उनकी वीरता, अनुशासन और युद्ध लड़ने की भावना पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हमारी राष्ट्रीय इच्छाशक्ति को मजबूत करेगी। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी वीरता, समर्पण और देशभक्ति ने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया और हर नागरिक को प्रेरित करती रहेगी।

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना की 'स्वदेशीकरण के माध्यम से सशक्तीकरण' पहल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, सामरिक दृढ़ता और आधुनिक युद्ध शैली के प्रभावी उपयोग का परिचय दिया जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत है।''

आईपीएल 26 मार्च से 31 मई के बीच होगा

मुंबई/भाषा। इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सत्र 26 मार्च से 31 मई की विंडो (टूर्नामेंट के लिए निर्धारित समय) के बीच होगा लेकिन यह देखना होगा है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) अपने घरेलू मैदान बेंगलूरु में टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी कर पाएगा या नहीं। नियमों के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। हालांकि इस आयोजन स्थल को कर्नाटक राज्य सरकार ने शर्तिया स्वीकृति दी है लेकिन इस साल जून में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद इसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा।आईपीएल 2026 के लिए छोटी नीलामी आज अबुधाबी में होगी जिसमें तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सबसे अधिक धनराशि के साथ उतरेगी।

कृत्रिम मेधा के युग में भारत की विविधता एक ताकत : प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) के युग में भारत की भाषाई एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता एक ताकत है। उन्होंने साथ ही कहा कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व कृषि में यहां विकसित किए गए समाधान अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं।

'प्रौद्योगिकी' को राष्ट्रीय बदलाव का एक रणनीतिक चालक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुमानों से संकेत मिलता है कि एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 1,700 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकता है।

प्रधान ने गूगल के 'लैब टू इम्पैक्ट' कार्यक्रम में कहा, '' एआई केवल आर्थिक मूल्य के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय क्षमता के बारे में है। यह इस बारे में है कि हम प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं या केवल उसका उपभोग करते हैं।

गांधी के विचारों से प्रधानमंत्री को नफरत!

जनविरोधी विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

▪ मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोज़गारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह विधेयक ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी को भी खत्म करने का ज़रिया है : राहुल

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा के स्थान पर लगाए गए 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्रपिता के विचारों तथा गरीबों के अधिकारों से नफरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस 'जन विरोधी' विधेयक का सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर विरोध करेगी।

सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है - महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है - करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर, प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रधानमंत्री मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है।

कांग्रेस नेता का कहना था, ''मनरेगा की बुनियाद तीन मूल विचारों पर थी। पहला यह कि रोज़गार का अधिकार - जो भी काम मांगेगा, उसे काम मिलेग। दूसरा यह कि गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता और तीसरा विचार था कि केंद्र सरकार मज़दूरी का पूरा खर्च और समान की लागत का 75 प्रतिशत देगी''

राहुल गांधी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ़ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया, '' बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा, राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा और बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा।''

रुपया टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 91.01 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई/भाषा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 91.01 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई सफलता न मिलने और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से रुपए की विनिमय दर में गिरावट आई है। कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले अपने पिछले बंद भाव से 36 पैसे टूटकर 91.14 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था लेकिन अंत में इसमें कुछ सुधार हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद भी स्थानीय मुद्रा में गिरावट को रोका नहीं जा सका। रुपया पिछले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 90 से गिरकर 91 पर आ गया। यह पिछले पांच सत्र में ही डॉलर के मुकाबले एक प्रतिशत लुढ़का है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपए के इस महीने 92 के स्तर को पार करने का अनुमान है।

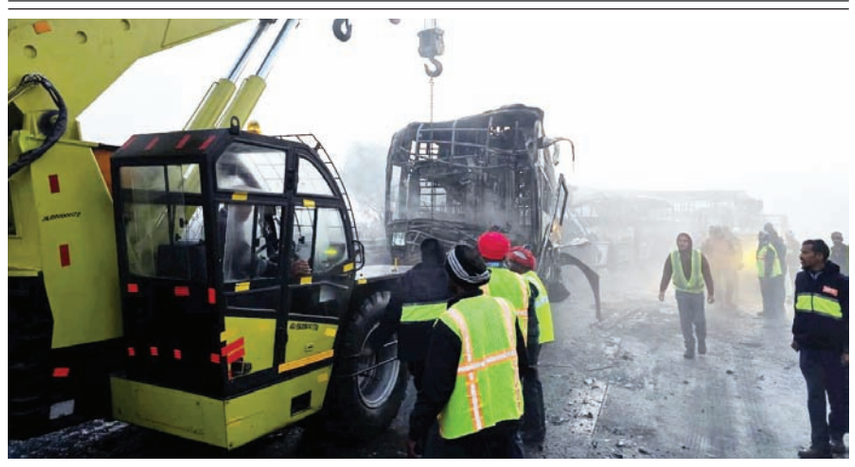

यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन टकराए, 13 लोगों की मौत व 35 अन्य घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मथुरा (उप्र)/भाषा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सात बस व तीन गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद कई वाहनों में लगी आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 35 अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

इस बीच जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे दो दिनों के भीतर तफ्तीश पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के आगरा-नोएडा साइड पर मंगलवार तड़के हुए हादसे की जांच के लिए मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार को नामित किया है। उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में तब हुआ जब घने कोहरे में आठ बस और तीन छोटे वाहन आपस में टकरा गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने कहा, ''आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हो गई।'' उन्होंने बताया कि संभवत: कोहरा होने से कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

17-12-2025 सूर्यास्त 5:45 बजे	18-12-2025 सूर्योदय 6:24 बजे
BSE 84,679.86 (-533.50)	NSE 25,860.10 (-167.20)
सोना 13,940 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 215,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

क्रिकेट क्यों

जिनकी सिम में बेलेंस नहीं,
उनसे भी करते रहें चैट।
जिस घर के द्वार बँधे कुत्ते,
क्यों जाएं उस दर खोल गेट।
खेलों से बढ़ता भ्रातृभाव,
बढ़ती मन की रन फ्लेट रेट।
जिनके मन में है बैर भाव,
उनके सँग भी खेलें क्रिकेट ।

भारत और इजराइल की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरूशलम/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताहांत यहूदी पर्व हनुक्का का जश्न मना रहे लोगों पर हुए आतंकवादी हमले की मंगलवार को कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल, दोनों की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। जयशंकर इजराइल की दो दिवसीय यात्रा के तहत मंगलवार को तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने अपने इजराइली समकक्ष गिदोन मोशे सार के साथ संवाददाताओं से बातचीत की।

जयशंकर ने कहा, सबसे पहले, मैं बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकवादी हमले में जानमाल के नुकसान पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं।

सिडनी के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताहांत यहूदी पर्व हनुक्का का जश्न मना रही भीड़ पर दो हमलावरों की ओर से की गई गोलीबारी में 15 लोग मारे गए थे और 40 अन्य घायल हो गए थे।

जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के सहयोग के लिए इजराइल का आभार जताया। उन्होंने कहा, भारत और इजराइल, हम दोनों ऐसे देश हैं, जिनकी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में निरंतर समर्थन के लिए आपके आभारी हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि वह और गिदोन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे, जो पिछले दशक में वास्तव में बहुत मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल एक-दूसरे के परस्पर साझेदार हैं और हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए।

जयशंकर ने गाजा शांति योजना के लिए भारत का समर्थन दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अदीस अबाबा/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कहा, ''हम भारत और इथियोपिया के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। यह कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा।'' उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री अली को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा, ''आतंकवाद के खिलाफ इस संघर्ष में मित्र देशों का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज हमें अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य और बहुपक्षीय सहयोग जैसे हमारे सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि आज हमने भारत में इथियोपिया के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को दोगुना करने का निर्णय लिया है।''

मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से संपर्क, संवाद और आदान-प्रदान होता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा और परंपराओं से समृद्ध ये दोनों देश विविधता में एकता के प्रतीक हैं। मोदी ने कहा, ''दोनों देश लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो शांति और मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने 18 बस यात्रियों का अपहरण किया

कराची/भाषा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने 18 लोगों का अपहरण कर लिया। ये सभी यात्री एक बस में क्वेटा जा रहे थे। पुलिस के अनुसार बाद में 10 यात्रियों को मुक्त करा लिया गया । सोमवार रात घोटकी इलाके के पास हमलावरों ने सिंध-पंजाब सीमा के करीब हाईवे लिंक रोड पर बस पर गोलियां चलाईं और 18 पुरुष यात्रियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी में चालक और कुछ यात्री घायल हो गए। जियो न्यूज के अनुसार, बस में यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने बताया कि घटनास्थल पर कुल 18- 20 हमलावर थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। महिला यात्री ने बताया कि हमलावरों ने 25 यात्रियों को बस से उतरने के लिए कहा, लेकिन महिला यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंध के गृह मंत्री के प्रवक्ता जिया उल हसन लांझर ने बताया कि ड्राइवर और खलासी के अलावा बस में करीब 30 यात्री सवार थे। डीआईजी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को 10 यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की।

बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से एटीएफ बिक्री 4.1 प्रतिशत घटी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। इस महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से दिसंबर के पहले पखवाड़े में विमान ईंधन (एटीएफ) की बिक्री चार प्रतिशत से अधिक घट गई। उद्योग के शुरुआती आंकड़ों से मंगलवार को यह जानकारी मिली।

कोविड महामारी से पैदा हुए व्यवधानों से उबरने के बाद पिछले दो वर्षों से भारत में विमान ईंधन या एटीएफ की मांग लगातार बढ़ रही थी। हालांकि बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से दिसंबर 2025 में यह सिलसिला टूट गया।

इंडिगो पायलट के नये कार्य अवधि नियमों, चालक दल की कमी और सर्दियों में धुंध जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। एयरलाइन ने कुल मिलाकर लगभग 5,000 उड़ानें रद्द कीं।

एटीएफ की बिक्री 1-15 दिसंबर तक 3,31,400 टन रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,45,400 टन था। मासिक आधार पर बिक्री में 7.2 प्रतिशत की गिरावट आई।

विमान ईंधन के विपरीत समीक्षाधीन अवधि में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे अन्य प्रमुख ईंधन की बिक्री बढ़ी। डीजल की बिक्री सालाना आधार पर लगभग पांच प्रतिशत बढ़कर 33 लाख टन हो गई। त्योहारी मांग कम होने से इसमें मासिक आधार पर 5.5 प्रतिशत की कमी हुई।

दिसंबर के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 13.3 लाख टन रही। मासिक आधार पर इसमें 5.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

एलपीजी बिक्री 15.5 लाख टन रही, जो सालाना आधार पर 15.1 प्रतिशत अधिक है। मासिक आधार पर बिक्री 4.4 प्रतिशत बढ़ी।

बीमा विधेयक का लक्ष्य दायरा और पारदर्शिता बढ़ाना है : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले विधेयक का लक्ष्य दायरे को व्यापक करना है और सरकार नियामक को और सुदृढ़ करना चाहती है।

सीतारमण ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' को लोकसभा में चर्चा और पारित के लिए रखते हुए कहा कि बीमा रकम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है और अनुपालन संबंधी कई नियमों को आसान किया गया है।

उन्होंने कहा, ''हम इसका (बीमा का) दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं और हम यह भी चाहते हैं कि नियामक और

सुदृढ़ हो, जिस कारण यह संशोधन लाया गया।''

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे बीमा क्षेत्र में एक बेहतर नियामक निगरानी होगी, अनुपालन आसान होगा, बीमा मध्यस्थ निर्बाध सेवाएं प्रदान करेंगे तथा बीमा और मध्यवर्ती कंपनियों, दोनों के साथ एक मानक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का लक्ष्य पारदर्शिता लाना है।

कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, ''विधेयक साढ़े 12 बजे पेश किया गया और हम साढ़े चार बजे इस पर चर्चा कर रहे हैं।'' उन्होंने सवाल किया, ''सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है?''

टैगोर ने कहा कि बीमा केवल पॉलिसी और प्रीमियम तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह जोखिम संभालने के लिए है। उन्होंने सवाल किया, '' 'प्रोटक्शन' अधिकार है या 'प्रोडक्ट' है?'' उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाजार के बजाय गणराज्य को, निगमों के बजाय नागरिकों को और लाभ से अधिक (लोगों के) 'प्रोटेक्शन' को चुना है।

कांग्रेस सदस्य ने एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, ''यह आवश्यकता से प्रेरित निर्णय नहीं, बल्कि विचाराधारा से प्रेरित है।''

एलआईसी का निवेश हासिल करने वालों में टाटा समूह, रिलायंस और अदाणी शीर्ष पांच में शामिल

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सबसे अधिक 88,404 करोड़ रुपए का निवेश टाटा समूह में किया है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक और रिलायंस समूह है जिनमें क्रमश: 80,843 करोड़ रुपए और 60,065.56 करोड़ रुपए निवेश किये गये हैं। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को दी। उन्होंने बताया कि एलआईसी ने अदाणी समूह में 47,633.78 करोड़ रुपए जबकि भारतीय स्टेट बैंक में 46,621.76 करोड़ रुपए का निवेश किया। उन्होंने बताया कि 35 घरेलू कंपनियां या समूह हैं जिनमें एलआईसी ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जो कुल मिलाकर 7.87 लाख करोड़ रुपए है। चौधरी ने उन समूहों की सूची भी साझा की जिनमें एलआईसी का संयुक्त निवेश 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस सूची में एल एंड टी, यूनिलीवर, आईडीबीआई बैंक, एम एंड एम और आदित्य बिरला शामिल हैं।

महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे हैं: प्रियंका

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी उनके परिवार के नहीं थे, लेकिन उनके परिवार जैसे ही हैं तथा पूरे देश की भावना भी यही है। उन्होंने सदन में 'विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025' को पेश किए जाने का विरोध करने के दौरान यह टिप्पणी की। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य जब इस विधेयक में महात्मा गांधी का नाम नहीं होने को लेकर सरकार की आलोचना कर रही थीं तो सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने कहा कि ''महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे।'' इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, ''हां, महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं। यही भावना पूरे देश की है।''

लद्दाख ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और केंद्र ने अब तक 10 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है।

शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है, जिसमें 2,12,280 की ग्रामीण जनसंख्या शामिल है।

इस केंद्र शासित प्रदेश में 169 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पीएसीएस) हैं, जिनमें से 129 वर्तमान में कार्यरत हैं और पीएसीएस से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं।

शाह ने कहा, ''कम आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद लद्दाख ने सहकारी समितियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है; लद्दाख की हर पंचायत में एक कार्यरत पीएसीएस है।''

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, ''सहकारी आंदोलन को व्यापक और विस्तारित करने के 'सहकार से समृद्धि' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, लद्दाख ने पीएसीएस के लिए आदर्श उपनियमों को अपनाया है, जिससे वे पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाते हुए 25 से अधिक विविध व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित कर सकेंगे।''

बीज विधेयक 2025 किसानों और पारंपरिक बीज किस्मों पर लागू नहीं होगा: सरकार

नई दिल्ली/भाषा। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि प्रस्तावित 'राष्ट्रीय बीज विधेयक-2025' किसानों और उनकी पारंपरिक बीज किस्मों पर लागू नहीं होगा और इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के अपने खेत में बचाए गए बीजों को सुरक्षित रखने, उनका आदान-प्रदान करने तथा बेचने के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

ठाकुर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किसान संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया है। ठाकुर ने कहा, ''विधेयक के प्रावधान किसानों और इनके द्वारा विकसित किस्मों पर लागू नहीं होते हैं, जिनमें पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं। यह विधेयक पादप किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अनुरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है।

जगन ने विजयवाड़ा में 42 मकानों को गिराये जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विजयवाड़ा/भाषा। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने जोजी नगर में हाल में 42 मकानों को गिराये जाने के मामले में मंगलवार को सीबीआई जांच की मांग की और आरोप लगाया कि इसमें सरकार के भीतर अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता है। जगन ने आज घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। जगन ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर कानूनी सहायता का आश्वासन भी दिया।

इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने से ही सच्चाई सामने आएगी और इन कृत्यों के पीछे उच्च पदों पर बैठे लोगों की भूमिका का खुलासा होगा।''

विजयवाड़ा नगर निगम के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि इन मकानों को गिराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

जगन के अनुसार 2.1 एकड़ के भूखंड पर रहने वाले 42 परिवारों के पास सभी आवश्यक अनुमति थी और वे आवास ऋण पर समान मासिक किस्तें (ईएमआई) चुका रहे थे, जब उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस भूखंड की कीमत कथित तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपए है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, आईटी मंत्री नारा लोकेश और अन्य स्थानीय नेताओं पर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ''इस कार्रवाई का समर्थन करने'' का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के अंतरिम राहत आदेश के बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विध्वंस की कार्रवाई की गई।

भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट सफलता की कहानी : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, और यह भारत की सफलता की विभिन्न कहानियों में से एक है। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ''मातृ मृत्यु दर में गिरावट भारत की सफलता की कहानियों में से एक है।''

पटेल ने गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ''इन कदमों का प्रभाव यह रहा है कि आज, भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट की दर वैश्विक गिरावट दर को पार कर गई है। हमारे यहां गिरावट की दर 86 प्रतिशत है, वहीं वैश्विक गिरावट केवल 48 प्रतिशत है।'' उन्होंने बताया कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2021-23 के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म 88 हो गई है जो पहले 130 थी।

पटेल ने कहा, ''...मैं बस यह कहना चाहती हूं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्रयास जारी हैं, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।''

बदलाव काम करने से आएगा, नाम बदलने से नहीं : मुख्यमंत्री मान

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए और अब देश का नाम बदलना बाकी है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मान ने यह बात ग्रामीण रोजगार के लिए 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025' से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कही, जिसे विपक्ष की आपत्तियों के बीच लोकसभा में पेश किया गया।

इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना और 20 साल पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लेना है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, ''उन्होंने रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदल दिए। अब सिर्फ देश का नाम बदलना बाकी है।'' उन्होंने साथ ही यह भी आशंका जताई कि कहीं देश का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर न रख दिया जाए।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने वायु प्रदूषण को लेकर माफी मांगी

पिछली आप सरकार पर ठीकरा फोड़ा

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण संकट को लेकर माफी मांगी और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि यह पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का परिणाम है। सिरसा ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि वर्तमान सरकार प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ''बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। हम इसे हर रोज कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सरकार नौ से दस महीनों के भीतर प्रदूषण के स्तर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती।

प्रदूषण के मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए सिरसा ने कहा कि वे इस संकट से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया, ''उन्होंने (आप नेताओं ने) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया और अब उस स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद पैदा किया है। पिछले 10 वर्षों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर लगभग एक जैसा ही बना हुआ है।''

गोवा नाइटक्लुब अग्निकांड: लूथरा बंधु थाईलैंड से प्रत्यर्पित, पुलिस हिरासत में लिया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद मंगलवार को दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

उत्तरी गोवा के अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने के 10 दिन बाद, दोनों भाई इंडिगो की उड़ान से दिल्ली लाए गए और उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए तुरंत अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। गौरव (44) और सौरभ (40) को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां गोवा पुलिस उनकी 'ट्रांजिट रिमांड' का अनुरोध करेगी। हवाई अड्डे पर उनसे पूछताछ की गई, जहां औपचारिकताएं पूरी करने में कई घंटे लग गए। उस विमान में कई पत्रकार और कैमरामैन यात्रा कर रहे थे। बैंकॉक से लूथरा बंधुओं पर नजर रखे एक टीवी रिपोर्टर ने विमान के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश की, जिसके बाद विमानन कंपनी और साथ आए सुरक्षा अधिकारियों को दोनों को वहां से निकालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाना पड़ा।

छह दिसंबर की घटना के बाद लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब द्वारा अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह घटना और भी गंभीर हो गई। इस घटना ने प्रबंधन द्वारा कथित अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों और चूक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक 260 करोड़ रुपए के गिरवी रखे शेयर छुड़ाएंगे

नई दिल्ली/भाषा। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने मंगलवार को कंपनी में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचा। सूत्रों के अनुसार इस बिक्री से मिली राशि से प्रवर्तकों के गिरवी रखे शेयरों (कुल 260 करोड़ रुपए) को छुड़ाया जाएगा। इस लेनदेन के लिए प्रवर्तक की हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेचा गया और कुछ राशि व्यक्तिगत आय से जुटाई गई। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 की तिमाही के अंत तक प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की पास ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में 36.78 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सूत्रों ने कहा कि अग्रवाल के व्यक्तिगत हिस्सेदारी का एक छोटा हिस्सा बेचने से गिरवी रखे 3.93 प्रतिशत शेयरों को पूरी तरह मुक्त किया जा सकेगा। इससे संस्थापक- प्रवर्तक कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद कंपनी में प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी लगभग 34 प्रतिशत रह जाएगी। सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तक द्वारा आगे कंपनी के शेयर गिरवी रखने की कोई योजना नहीं है। एआई स्टार्टअप 'क्रुत्रिम' के वित्त पोषण के लिए मौजूदा शेयर गिरवी रखे गए थे, जो अब सकारात्मक नकदी प्रवाह दिखा रहा है।

विधानसभा में ग्रेटर बेंगलूरु प्रशासन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पारित

बेलगावी। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधानसभा से ग्रेटर बेंगलूरु प्रशासन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार करने और उसे पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा करना और कुछ संशोधन करना उचित समझा गया। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने संशोधनों सहित विधेयक पारित करने का अनुरोध किया। विधेयक पारित हो गया। कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक भूमि राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 का पारित होना।

राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विधानसभा से अनुरोध किया कि वह कर्नाटक विधानसभा की जांच समिति द्वारा अनुशंसित कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2025 और कर्नाटक भूमि राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार करे और उन्हें पारित करे। कर्नाटक भूमि राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विधानसभा की जांच समिति के पास भेजा गया। राजस्व मंत्री ने बैठक में बताया कि यह विधेयक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अदालतें आयोजित करके और कोडागु जिले में विधेयक पर जनमत संग्रह करके जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि यह विधेयक स्वागत योग्य है और समिति की बैठक में इस पर 5-6 बार चर्चा हो चुकी तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी विधायकों ने इस विधेयक को पारित करने पर सहमति जताई है। उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयक को लागू करते समय इसके मसौदे तैयार किए जाने चाहिए। विधायक अरविंद बेल्लाड ने कहा कि विधेयक के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाते समय, बेहतर होगा कि नियमों को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए और नियम बनाने से पहले समिति की राय ली जाए।

रेवंत रेड्डी ने केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की शिक्षा परियोजनाओं पर समर्थन मांगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर शिक्षा क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों के लिए केंद्र का समर्थन मांगा। इनमें हैदराबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

तेलंगाना सरकार ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और हाल ही में आयोजित 'तेलंगाना राइजिंग वैश्विक सम्मेलन' से संबंधित ब्योरों से अवगत कराया।

इस मुकालात में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ की।

रेड्डी ने सीतारमण को 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल' योजना की भी जानकारी दी, जिसमें राज्य के 105 विधानसभा क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोल जाने हैं। हरेक स्कूल में पांचवीं से लेकर 12वीं कक्षा तक कुल 2,560 छात्र पढ़ेंगे। इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से 2.70 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में कहा कि इन 105 स्कूलों के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए और जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 9,000 करोड़ रुपए की जरूरत है।

रेड्डी ने कहा कि इन स्कूलों के लिए गठित किए जा रहे विशेष प्रयोजन केंद्र के जरिये जुटाए जाने वाले ऋण को राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा से बाहर रखा जाए। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि शिक्षा को मानव संसाधन विकास में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। बयान के मुताबिक, वित्त मंत्री ने तेलंगाना सरकार की इस पहल की सराहना की और विशेष प्रयोजन केंद्र के विवरण मांगे।

रेड्डी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के दौरान हैदराबाद में आईआईएम की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में 200 एकड़ भूमि आईआईएम के लिए चिह्नित की है और उस ट्रांज़िट परिसर से इसकी कक्षाएं तत्काल शुरू की जा सकती हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नौ केंद्रीय विद्यालयों और 16 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की भी मांग की। राज्य सरकार ने इन संस्थानों के लिए भूमि और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर गोलीबारी का संदिग्ध मूल रूप से हैदराबाद का निवासी था : पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताहांत हुई गोलीबारी में शामिल संदिग्धों में से एक साजिद अकरम मूल रूप से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का रहने वाला था। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय साजिद भले ही 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गया था, लेकिन उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। साजिद बॉन्डी बीच पर पुलिस कार्रवाई के दौरान मारा गया था। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, साजिद नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और उसका हैदराबाद में रहने वाले अपने परिवार से सीमित संपर्क था।

बयान में कहा गया है, साजिद मूल रूप से हैदराबाद (भारत) का रहने वाला था। उसने हैदराबाद से बी.कॉम की डिग्री हासिल की और फिर रोजगार की तलाश में लगभग

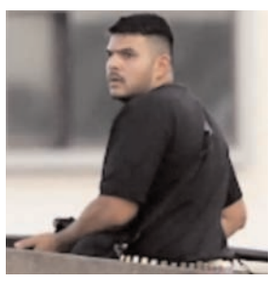

27 साल पहले नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया।

इसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में साजिद ने यूरोपीय मूल की एक महिला से शादी कर ली और वहीं बस गया। बयान के अनुसार, ''दंपति के दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी)हैं। इनमें से एक नवीद अकरम (24) बॉन्डी बीच के दो संदिग्ध हमलावरों में शामिल है।'' इसमें कहा गया है कि नवीद और उसकी बहन का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तथा दोनों वहीं के नागरिक हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर पिछले सप्ताहांत यहूदी पर्व हनुक्का का जश्न मना रही भीड़ पर हुई गोलीबारी में 15 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस आयुक्त क्रिसी बैरेट ने मंगलवार को कहा कि यह गोलीबारी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला थी। ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के मुताबिक, गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का संदेह एक पिता-पुत्र पर है, जिनकी उम्र क्रमशः 50 साल और 24 साल है। उन्होंने बताया कि पिता-पुत्र की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है। प्राधिकारियों के अनुसार, साजिद घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई में मारा गया था।

धर्मपुरी के पास सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

धर्मपुरी। धर्मपुरी के पास एक राज्य राजमार्ग पर मंगलवार को एक ट्रक ने दोपहिया वाहन और कार को टक्कर मार दी। इन हादसों में महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दो घायलों को धर्मपुरी जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया सेलम जा रहे ट्रक का चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और इसने दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद यह ट्रक विपरीत दिशा से आ रही एक कार से टकराया। अधिकारी ने बताया, चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतकों में वी. कलैरासी, पी. दिनेश, एस. मुनियाप्पन और ट्रक चालक अरुणागिरी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय पर न्यायालय का फैसला द्रमुक सरकार के लिए झटका : भाजपा नेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने तमिलनाडु स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को समान शिक्षा के ''अधिकार को छीनने वाली'' द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के लिए मंगलवार को ''बड़ा झटका'' बताया। नागेंद्रन ने कहा कि यदि सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार हमेशा की तरह इस आदेश का भी अनादर करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों द्वारा गठित होने वाली ''सरकार'' पूरे तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय शुरू करेगी।

नागेंद्रन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''हम राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट बनाएंगे। यह निश्चित रूप से होगा।'' न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के मुद्दे पर केंद्र के साथ विचार- विमर्श करने का सोमवार को निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार को टकराव का रवैया नहीं अपनाना चाहिए और एक संघीय प्रारूप में चर्चा होनी चाहिए। पीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को कहा। नागेंद्रन ने कहा, समान शिक्षा के अधिकार को छीनने के लिए उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक सरकार को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सवाल किया है कि राज्य सरकार ने ''तुच्छ राजनीति'' के कारण उन जवाहर नवोदय विद्यालयों को स्थापित होने से क्यों रोका, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को निःशुल्क आवास और भोजन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। नागेंद्रन ने कहा कि देशभर में 650 नवोदय विद्यालयों से हजारों ग्रामीण छात्रों को लाभ मिला है और अदालत ने सही कहा कि भाषा के आधार पर उन्हें शिक्षा से वंचित करना और उनकी प्रगति को रोकना अनुचित है। नागेंद्रन ने कहा, ''गरीब ग्रामीण छात्रों का भविष्य कई वर्षों तक बर्बाद करने के पाप के प्रायश्चित के रूप में द्रमुक सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हर जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए।''

तिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम् प्रज्वलन मामले का परोक्ष उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''द्रमुक सरकार यदि हमेशा की तरह अदालत के आदेश का अनादर भी करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।'' उन्होंने कहा, ''जो राजग सरकार बनेगी, वह पूरे तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय शुरू करेगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी और छात्रों को उत्कृष्ट बनाएगी। यह निश्चित है।''

पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर 'प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता': अदालत में बोली तमिलनाडु सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी को क्लीन चिट देते हुए, तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जनरल पी एस रमन ने यह बात कही।

रमन ने बताया कि सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने विस्तृत जांच की और पाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में पलानीस्वामी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि सतर्कता आयुक्त को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिन्होंने इसे राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और पलानीस्वामी के खिलाफ सुनवाई रोक दी।

पीठ ने मामले की सुनवाई क्रिसमस की छुट्टियों के बाद के लिए स्थगित कर दी। ऐसा याचिकाकर्ता के वकील को न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में अपनी दलीलें पेश करने का मौका देने के लिए किया गया है। अपनी याचिका में एन राजशेखरन ने कहा कि पलानीस्वामी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सरकार ने राज्य के 11 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया था। परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर गबन और भ्रष्टाचार हुआ, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत अपराध के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने एक याचिका दायर की और जब उस पर सुनवाई हुई, तो सरकार ने अदालत को सूचित किया कि प्रारंभिक जांच के बाद विस्तृत जांच की जा रही है।

भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रौद्योगिकी, मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत : राष्ट्रपति मुर्मू

मंड्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में देश को प्रौद्योगिकी और मूल्यों, दोनों की ताकत की जरूरत है। मुर्मू कर्नाटक के मंड्या जिले के मालवल्ली में आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर शिवयोगी महास्वामीजी के 1066वें जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बोल रही थीं।

उन्होंने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, हमें प्रौद्योगिकी और मूल्यों, दोनों की ताकत की जरूरत है। एक विकसित भारत के लिए आधुनिक शिक्षा को नैतिक ज्ञान के साथ, नवाचार को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ, आर्थिक विकास को सामाजिक समावेश के साथ और प्रगति को करुणा के साथ एकीकृत करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार समावेशन, सेवा और मानवीय गरिमा पर आधारित भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मुर्मू ने युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, जिसका भविष्य न केवल युवाओं के कौशल और ज्ञान से, बल्कि उनकी ईमानदारी और उद्देश्य की भावना से भी आकार लेगा। उन्होंने कहा, युवा-उनकी ऊर्जा, रचनात्मकता, मूल्य और चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। भारत का भविष्य न केवल युवाओं के कौशल और ज्ञान से, बल्कि उनकी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से भी सुरक्षित होगा। मुर्मू ने कहा कि महास्वामीजी का जीवन और शिक्षाएं एक हजार से अधिक वर्षों के बाद भी अनगिनत लोगों को प्रेरणा देती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं।

उन्होंने कहा कि युगों-युगों तक संतों ने ज्ञान और करुणा के माध्यम से मानवता को प्रबुद्ध किया है और समाज को याद दिलाया है कि सच्ची महानता अधिकार या धन में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। दसवीं शताब्दी में सुत्तूर में जगद्गुरु श्री वीरसिंहासन महासंस्थान मठ की स्थापना को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जो एक पवित्र आध्यात्मिक केंद्र के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे सामाजिक बदलाव के लिए एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने कहा कि यह मठ एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जिसने कई पीढ़ियों में अनुशासन, भक्ति और करुणा के मूल्यों का संचार किया।

दक्षिणी रेलवे रेल खंडों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां दक्षिणी रेलवे में विद्युतीकरण का कार्य 1931 में चेन्नई उपनगरीय खंड से शुरू हुआ था। हाल के वर्षों में, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के कई महत्वपूर्ण मार्गों को चालू किया गया है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हुई है और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिला है। दक्षिणी रेलवे ने रेलवे विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है, और 15 दिसंबर तक अपने कुल नेटवर्क के 97 प्रतिशत से अधिक का विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। दक्षिणी रेलवे ने अपने नेटवर्क के 97.63 प्रतिशत हिस्से, यानी 5,116 किलोमीटर में से 4,995 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। दक्षिणी रेलवे लगभग पूरी तरह से विद्युतीकृत होने की ओर अग्रसर है, जो टिकाऊ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। नेटवर्क का केवल 53 आरकेएम हिस्सा तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसमें मेट्टुपालयम-उदगमंडलम पहाड़ी खंड (यूनेस्को-सूचीबद्ध विरासत पर्वतीय रेलवे) और नौसेना वायुसेना अड्डे के पास एर्नाकुलम और कोच्चि हार्बर टर्मिनस के बीच का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। इन खंडों को छोड़कर, दक्षिणी रेलवे का कुल विद्युतीकरण योग्य नेटवर्क 5,075 आरकेएम है, जिसमें से केवल 132 आरकेएम का विद्युतीकरण होना बाकी है।

तिरुतुरईपुंडी-पट्टुक्कोट्टई- कराईकुडी (120 आरकेएम), चिन्ना सेलम-पोरपाडाकुरिची (12 आरकेएम) के शेष विद्युतीकरण कार्य 2026-27 तक पूरा होने के लिए निर्धारित हैं। दक्षिणी रेलवे के छह डिवीजनों में से चेन्नई, मदुरै, पलक्कड़ और तिरुवनंतपुरम डिवीजनों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। सेलम और तिरुचिरापल्ली डिवीजनों में क्रमशः 98 प्रतिशत और 88 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। दक्षिणी रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण खंडों में विद्युतीकरण की समयरेखा को दर्शाने वाला एक मानचित्र संदर्भ के लिए संलग्न है।

हैदराबाद में एक महिला ने अपनी बेटी को इमारत की चौथी मंजिल से फेंका

हैदराबाद। हैदराबाद में 37 वर्षीय एक महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी आठ वर्षीय बेटी को एक आवासीय इमारत की चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मलकाजगिरि पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार दोपहर को हुई, जिसके परिणामस्वरूप लड़की की मौत हो गई।

अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि निजी कर्मचारी के रूप में काम करने वाली महिला रविवार रात से अपने परिवार के सदस्यों के साथ हुए झगड़ों के बाद मानसिक रूप से ''परेशान'' थी। उसने सोमवार को अपनी बेटी को इमारत की चौथी मंजिल पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

जलाहल्ली अंडरपास के काम को लेकर शीघ्र ही सभी के साथ होगी बैठक : उपमुख्यमंत्री शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, जलाहल्ली अंडरपास के काम को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं की अध्यक्षता में संबंधित विधायक और अधिकारियों की बैठक होगी। शिवकुमार मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विधायक मुनिराजू के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

जलाहल्ली अंडरपास का काम शुरू होने और कुछ के पेंडिंग मुआवज़े के बारे में मुनिराजू के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा, हमने यह अंडरपास का काम पीजीबी नाम की एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया है। वर्ष 2021 में, यह काम 57 करोड़ की ग्रांट के साथ सौंपा गया था। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में 48 प्रॉपर्टी मालिकों को मुआवज़ा दिया जा चुका है। कुल 85 करोड़ मुआवज़े के तौर पर दिए जा रहे हैं। यहां ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का अनुमान 139 करोड़ लगाया गया है। दूसरे 26 ज़मीन मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी देनी है, जिसके लिए 53 करोड़ मुआवज़े के तौर पर देने हैं। मुआवजे के तौर पर टीडीआर या पैसा देना होगा। अगर विधायक मुनिराजू इन प्रॉपर्टी मालिकों से बात करते हैं, तो उन्हें टीडीआर दिया जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। यह ट्रैफिक जाम वाला एक बड़ा इलाका है। इसलिए, उनकी मांग सही है।

इस बीच, मुनिरत्न ने मांग की कि हमारे इलाके में कई फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है और मंत्री को सभी विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए और हमारे निवेदन को मानना चाहिए। इसका जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा, विधायक मुनिराजू ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैंने उसका जवाब दे दिया है। विधानसभा में विधायक एस.टी. सोमशेखर के हॉलिडे विलेज रोड पर व्हाइट टॉपिंग के काम में देरी के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, बोम्मनहल्ली, बेंगलूरु साउथ और यशवंतपुर चुनाव क्षेत्र बेंगलूरु शहर के बहुत बड़े चुनाव क्षेत्र हैं। मैं खुद उनके चुनाव क्षेत्र में उस जगह गया था जहां काम हो रहा है। काम ओशन कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। मैं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर उससे बात करूंगा। हॉलिडे विलेज रोड का काम चल रहा है और इस एरिया में यूटिलिटी से जुड़ी कुछ दिक्कतें हैं। बीडब्ल्यूएसएसबी पावर लाइन को शिफ्ट करने की जरूरत है। इसलिए, इसमें देरी हो रही है।

कर्नाटक सरकार अंडों में कैंसरकारी पदार्थों के होने संबंधी दावों की जांच के लिए नमूने एकत्र कर रही

बेलगावी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एक विशेष ब्रांड के अंडों में 'जीनोटॉक्सिस पदार्थ' होने का दावा सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मंगलवार को कहा कि जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 'जीनोटॉक्सिस पदार्थ' डीएनए की संरचना में बदलाव कर सकते हैं।

विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रमेश बाबू द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रसारित हो रही सूचनाओं के आधार पर लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर किए गए दावों के अनुसार, प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने के बाद एक विशेष ब्रांड के अंडों में 'नाइट्रोफ्यूरान' और 'नाइट्रोइमिडाजोल' के अंश पाए गए हैं। 'नाइट्रोफ्यूरान' और 'नाइट्रोइमिडाजोल' का मुर्गी पालन में उपयोग कथित तौर पर प्रतिबंधित है। ये पदार्थ अंडों में मौजूद हो सकते हैं क्योंकि मुर्गी पालन के दौरान इनका उपयोग मुर्गियों को जीवाणु संक्रमण से बचाने के साथ ही मुर्गियों के अंडे देने की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। राव ने कहा, अंडों को लेकर काफी चर्चा हो रही है और हम इस बारे में पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। पिछले साल हमने अंडों के 124 नमूनों की जांच की थी, जिनमें से 123 अच्छी गुणवत्ता के पाए गए और केवल एक नमूने में गुणवत्ता संबंधी समस्या थी। सोशल मीडिया पर अंडों को लेकर हाल ही में आई खबरों के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी या ब्रांड के बारे में यह शिकायतें आई हैं वहां से अंडों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। इसी तरह, अन्य जगहों से भी अंडों के नमूने एकत्र किए गए हैं। राव ने कहा, 'रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग सकते हैं और रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को अंडों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेवजह कुछ खबरें सामने आई हैं जिन्हें प्रचारित किया गया है।'' उन्होंने कहा कि सरकार सावधानी बरतेगी और अंडों की जांच करवाएगी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के प्राधिकारियों को इस संबंध में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से भी बात करने को कहा है। एमएलसी बाबू ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए दावों ने लोगों को अंडों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित कर दिया है।

ग्राहकों को धोखा देकर सामान बेचने वाली 2334 कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए : मंत्री केएच मुनियप्पा

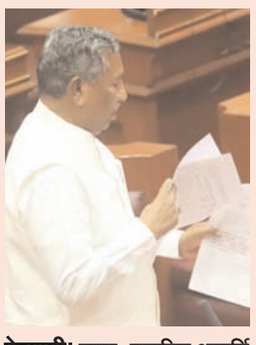

बेलगावी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा कानूनी मापशास्त्र मंत्री के. एच. मुनियप्पा ने कहा कि बेंगलूरु क्षेत्र में उपभोक्ताओं को धोखा देकर घरेलू उपकरण बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में घरेलू उपकरणों से संबंधित 2334 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2250 मामलों का निपटारा हो चुका है। मंगलवार को विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य रमेश बाबू द्वारा पूछे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु खरीदते समय या कोई सेवा प्राप्त करते समय धोखा दिया जाता है, तो उसके पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज करने और मुआवजा प्राप्त करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि होटलों में पैकेटबंद स्नैक्स/पानी की बोतलों पर सरकारी घोषणाओं के उल्लंघन और पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन के लिए कानूनी मापन (पैकेजिंग) नियम-2011 के तहत होटलों का निरीक्षण किया जाएगा, और नियमों के अनुसार मध्यस्थता शुल्क लिया जाएगा, और जो होटल मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं होंगे उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया जाएगा।

जब तक शीर्ष नेतृत्व चाहेगा मैं मुख्यमंत्री पद पर कायम रहूंगा : सिद्दरामय्या

बेलगावी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को फिर कहा कि जब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को पांच साल तक शासन के लिए जनादेश मिला है और वह (पार्टी) 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद भी सत्ता में वापसी करेगी।

सिद्दरामय्या ने विधानसभा में कहा, मैं यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हमारे पास शीर्ष नेतृत्व है। हम उनके फैसले का पालन करते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो कहे, वही अंतिम होता है, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेतृत्व का मुद्दा उठा। कुनिगल से कांग्रेस विधायक एच डी रंगनाथ ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसी बैंक) से अल्पकालिक ऋण नहीं मिल रहा है, जबकि पड़ोसी मधुगिरी निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को 100 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण प्राप्त हुए हैं। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के भरोसेमंद और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखने के आकांक्षी रंगनाथ ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सिद्दरामय्या के भरोसेमंद के एन राजन्ना को मधुगिरि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रंगनाथ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्दरामय्या ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि कोई भेदभाव हुआ है तो वे उसे दूर करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, उम्मीद है रंगनाथ मुझ पर भरोसा करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने तंज करते हुए कहा कि यह भेदभाव जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, आग में घी मत डालो। विपक्ष का काम तो आग में घी डालना ही है। अशोक ने उत्तर दिया, इसका मतलब है कि आग लगी है। रंगनाथ पूजा कर रहे हैं ताकि डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकें। अशोक ने यह भी कहा कि विपक्ष आग भड़का रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिंता की बात यह है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक ही अशांति फैला रहे हैं। सिद्दरामय्या ने अशोक को फटकारा और कहा कि जब सत्ताधारी विधायक चुप हैं तो उन्हें भी चुप रहना चाहिए। अशोक ने कहा, वे चुप नहीं बैठे हैं महोदय। वे प्रतिदिन पूजा-अर्चना कर रहे हैं। वे शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। मैं यह बात प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहा हूं। सिद्दरामय्या ने कहा, भले ही आप उकसाने की कोशिश करें, हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, सभी 140 विधायक एकजुट हैं। इसके बाद विपक्ष के नेता ने उनसे पूछा कि क्या वे पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके जवाब में सिद्दरामय्या ने कहा, आप मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जनता ने हमें पांच साल तक शासन करने का जनादेश दिया है।

नाबार्ड के अनुदान में 2185 करोड़ रुपये की कटौती हुई : मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या

बेलगावी। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बताया कि केंद्रीय नाबार्ड से वर्ष 2024-25 के लिए कम ब्याज दर पर 5600 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होना था। हालांकि, केवल 3415 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और 2185 करोड़ रुपये के अनुदान में कटौती की गई है। वे बेलगाव के सुवर्णा विधान सौधा में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में बोल रहे थे, जब उन्होंने कुनिगल के विधायक डॉ. एचडी रंगनाथ द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड अनुदान में कटौती के परिणामस्वरूप, कई विधानसभा क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हो गई है जहां कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं।

मदुगिरी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी 26 प्रतिशत है, जबकि कुनिगल निर्वाचन क्षेत्र में यह 8 प्रतिशत है। इस पृष्ठभूमि में अनुदान आवंटन में भेदभाव होता रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने इस भेदभाव को समाप्त करने और आगामी वर्ष में कुनिगल निर्वाचन क्षेत्र को नाबार्ड अनुदान आवंटित करने का वादा किया है। कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण योजना के तहत, राज्य सरकार ने कुनिगल तालुक की कृषि सहकारी समितियों को कंप्यूटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनर और यूपीएस सहित नेटवर्किंग उपकरण प्रदान करने के लिए प्रति समिति 1.30 लाख रुपये की दर से 24.70 लाख रुपये जारी किए हैं। तुमकुर डीसीसी बैंक के कुनिगल तालुक संघों ने 2024-25 में 14,850 किसानों को 40.33 करोड़ रुपये के अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 10,833 किसानों को 38.40 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो चुका है। 11 किसानों को 1.58 करोड़ रुपये के मध्यम अवधि/दीर्घकालिक कृषि ऋण दिए गए हैं। 2025-26 में तालुक के 13,750 किसानों को 40 करोड़ रुपये के अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, और नवंबर के अंत तक 2983 किसानों को 10.50 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण प्राप्त हो चुका है। 20 किसानों को 2 करोड़ रुपये के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, और 13 किसानों को मध्यम अवधि और दीर्घकालिक कृषि ऋण प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने अपने जवाब में कहा कि यह राशि 1.30 करोड़ रुपये है।

अरावली केवल पर्वत नहीं बल्कि राजस्थान का 'रक्षा कवच' है : अशोक गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली की पहाड़ियों को राजस्थान का 'रक्षा कवच' बताते हुए मंगलवार को कहा कि इसकी छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को निमंत्रण देना है। गहलोत ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। उन्होंने कहा, अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा 'रक्षा कवच' है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे '100 मीटर' के दायरे में समेटना, प्रदेश के 90 फीसदी अरावली के 'मृत्यु प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर करने जैसा है। कांग्रेस नेता ने कहा, सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। उनके अनुसार, इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है।

उन्होंने कहा कि एक छोटी चट्टान भी उसी 'टेक्टोनिक प्लेट' और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक ऊंची चोटी है और इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है। अरावली को थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार बताते हुए गहलोत ने कहा, विशेषज्ञों के मुताबिक 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है। उन्होंने कहा कि अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये पहाड़ियां पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं और इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है। गहलोत ने कहा कि यही नहीं अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है। उन्होंने कहा,यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए 'रेड कार्पेट' है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। गहलोत के अनुसार, विडंबना ये है कि उच्चतम न्यायालय में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को न्यायालय ने माना, उसने अरावली के 90 फीसदी हिस्से को ही तकनीकी रूप से 'गायब' कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं उच्चतम न्यायालय से आग्रह करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे।

अपराध पर अंकुश के लिए थानों का आधुनिकीकरण किया जाए : श्रीनिवास

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अपराध पर अंकुश के लिए थानों के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में अपराध के आंकड़ों में कमी आना 'शुभ संकेत' है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। वह यहां भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा राज्य में अपराधों के आंकड़ों में कमी शुभ संकेत है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के 'रिस्पांस टाइम' को कम करना, त्वरित अनुसंधान और थानों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी थानों का 'डिजिटलाइजेशन' करने के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने थानों में निर्बाध 'वाई-फाई' सुविधा के लिए सभी थानों में 'राज नेट' की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। एक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्य सचिव ने कहा कि थानों में महिला कांस्टेबल की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा 'ई साक्ष्य' ऐप का प्रयोग किया जा रहा है जिससे पुलिस को घटनास्थल के वीडियो, फोटो और गवाहों के बयान डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने की सुविधा मिली है।

विस्फोटक होने की धमकी के बाद अदालत परिसरों की तलाशी

जयपुर। विस्फोटक रखे होने की धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मंगलवार को यहां राजस्थान उच्च न्यायालय और सत्र अदालत परिसर की तलाशी ली। हालांकि सुरक्षाकर्मियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि सत्र अदालत की ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसमें दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चैंबर में विस्फोटक लगाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस के श्वान दस्ते व अन्य विशेषज्ञ टीमें पहुंची और दोनों परिसरों की अच्छी तरह से पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि जांच और तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिसके बाद इन परिसरों में कामकाज सुचारू हुआ। हाल के दिनों में उच्च न्यायालय और अन्य इमारतों में बम रखने होने की कई बार फर्जी सूचनाएं दी गई हैं।

अधिकांश जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा

जयपुर। राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार सोमवार रात न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 4.0 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री, दौसा में 6.2 डिग्री, सिरोही में 6.6 डिग्री और चूरू में 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में मंगलवार सुबह धुंध छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य बना रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का फैसला 'सत्ता पर सत्य की विजय' : अशोक गहलोत

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत के फैसले को 'सत्ता पर सत्य की विजय' का प्रमाण बताते हुए मंगलवार को कहा कि अंततः जीत सच्चाई की ही हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने 'नेशनल हेराल्ड' मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का फैसला 'सत्ता पर सत्य की विजय' का प्रमाण है। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें धन शोधन का कोई मामला नहीं बनता। कांग्रेस नेता ने कहा, हम शुरू से ही कह रहे थे कि यह मोदी सरकार द्वारा रचा गया एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार की छवि खराब करना था। कुछ दिन पहले ही इसीलिए ईडी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई, क्योंकि जब से चालान पेश किया गया था, तब से ही उन्हें पता था कि इस मामले में कोई दम नहीं है। गहलोत ने कहा, मोदी सरकार के दबाव में ईडी ने अदालत में अपनी भद्द पिटवाई है। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अंततः जीत सच्चाई की ही हुई है।

निर्दलीय विधायक ने 'राजनीतिक रूप से फंसाने' का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। विधायक निधि से पैसा जारी करने के लिए कमीशन मांगने के आरोप का सामना कर रही निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने सोमवार को आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है।' बयाना से इस विधायक ने दावा किया कि उन पर 2026 के लिए भी विधायक निधि से पैसा जारी करने के लिए पत्र देने का दबाव डाला गया था, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

एक अखबार के 'स्टिंग ऑपरेशन' में बनावत, खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा और हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए लैड) से पैसे मंजूर करने के बदले कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने आरोपों की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए। साथ ही, जांच के नतीजे आने तक इन विधायकों के विधायक निधि खातों को 'फ्रीज' कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले को सदन की आचार समिति को भेज दिया है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझसे बार-बार विधायक निधि के लिए पत्र देने को कहा गया, जबकि यह 2026 के लिए था। मैंने यह कहते हुए मना किया इससे मेरी छवि खराब होगी। मैंने कभी भी पत्र के बदले में किसी पैसे के लेन-देन के बारे में बात नहीं की। बनावत ने दावा किया कि जब उन्होंने यह आग्रह ठुकरा दिया तो उस व्यक्ति ने उनके पति से संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैं विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगी कि अगर मैं गलत हूं और दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन अगर मुझे राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति (रिपोर्टर) के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

विधायक ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और वह संबंधित अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। उन्होंने कहा, मैं विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाऊंगी। बनावत ने शंका जताई कि इस मुद्दे के 'राजनीतिक संपर्क' हो सकते हैं और इसमें 'ब्लैकमेल' करने वाले तत्व शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मुझे दूसरे विधायकों या व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो।

उल्लेखनीय है कि रविवार को राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधायक डांगा को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर उन पर लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि कांग्रेस ने जाटव को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम : तोमर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से 150 संभागियों ने भाग लिया जिसमें राष्ट्रीय पशुधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ अरुण तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन हिंदुस्तान की आवश्यकता है। जिसे पशुपालन के क्षेत्र में बड़े उद्यमी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पशुपालन के क्षेत्र में हम आज कई मामलों में नंबर एक पर हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ किए जाने की संभावना शेष है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है प्रति पशु उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए एक फार्मूला जी प्लस ई की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे प्रदर्शन के लिए पशुओं की नस्ल और उसके आधार पर उनका रखरखाव बहुत आवश्यक है। हमें अपने किसानों और पशुपालकों को यह बताना बहुत आवश्यक है कि किस जलवायु के लिए कौन सी नस्ल उपयुक्त है और किससे हम उत्तम उत्पादन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा अधिकारियों को केवल पशुओं की चिकित्सा तक ही खुद को सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि हमें पशुधन के संपूर्ण विकास की बात करनी चाहिए और अपनी भूमिका को विस्तार देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा पशु बीमार ही न हो। उन्होंने कहा कि पशुधन गणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके आधार पर सारी योजनाओं का निर्माण होता है। उन्होंने समय समय पर होने वाले इस तरह के प्रशिक्षण को पशु चिकित्सकों के साथ विभाग के लिए भी बहुत उपयोगी बताया।

पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में जो भी जानकारी लेकर यहां से जाएं उसे और लोगों तक भी पहुंचाएं और इसका लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को मिल सके ऐसा प्रयास सभी करें। उन्होंने कहा कियदि सही जानकारी सही समय पर पशुपालक तक पहुंच जाए तो उसका सीधा लाभ स्वास्थ्य, उत्पादन और आय बढ़ोतरी के रूप में मिलता है।

विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ प्रवीण कुमार सेन ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय पशुधन मिशन के विषय में सभी को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे फील्ड के लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पशुधन क्षेत्र (जैसे डेयरी, पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर) के सतत विकास के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की आय और जीवन स्तर में सुधार करना है, जिसमें उद्यमिता विकास, नस्ल सुधार, चारा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच बढ़ाना शामिल है, जिसके लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मुख्य सचिव सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को शासन सचिवालय में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ शासन सचिवालय परिसर में कर्मचारी संघ कैंटीन के समीप से किया गया। यहां मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के साथ वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। अभियान के अंतर्गत शासन सचिवालय में स्थित विभिन्न कार्यालयों सहित सभी राजकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साफ-सफाई की। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यालय परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल कार्यक्षमता बढ़ाता है, बल्कि सकारात्मक कार्य-संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने कहा कि फाइलों और रिकॉर्ड्स का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड्स की समय-समय पर समीक्षा (रिव्यू) एवं छंटनी (टाइमली वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स) की जानी चाहिये। साथ ही पुराने फर्नीचर, अनुपयोगी वाहन स्क्रैप का समय पर निस्तारण किया जाना चाहिये।

उन्होंने कहा कि पुराने और बेकार लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन आदि डिजिटल स्क्रैप का भी नियमानुसार निपटान किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अभय कुमार, शासन सचिव कार्मिक विभाग श्रीमती अर्चना सिंह, शासन सचिव युवा

फर्जी लोगों को चिन्हित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण जरूरी : अरुण चतुर्वेदी

जयपुर । राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को मौजूदा समय में जरूरी बताया। उन्होंने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। इसके तहत उन्हीं मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रहेगा, जो मूल रूप से भारत के निवासी हैं और उन्हें यहां की नागरिकता प्राप्त है, जिनके पास वैध दस्तावेज मौजूद हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ अर्जित करने के मकसद से यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में मदद की।

अपराधों पर अंकुश के लिए पुलिस थानों का आधुनिकीकरण किया जाए : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में अपराधों के आंकड़ों में कमी शुभ संकेत है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के रेस्पोंस टाइम को कम करना, त्वरित अनुसंधान और पुलिस थानों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी थानों का डिजिटलाइजेशन करने के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने थानों में निर्बाध और स्ट्रोंग वाई-फाई की सुविधा के लिए सभी पुलिस थानों में राज नेट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि थानों में महिला कॉन्स्टेबल की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि थानों में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट पेश करने के बीच निश्चित समय सीमा से ज्यादा समय नहीं लगे। श्रीनिवास ने कहा कि नये कानून के तहत अपराध कहीं भी हो उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाने में 'ज़ीरो ऋखठ' के रूप में दर्ज कराई जा सकती है। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकॉप एसओएस अलर्ट उपलब्ध है। महिलाओं के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश में राजकॉप नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन पर 'नीड हैल्प'सुविधा है। उन्होंने कहा कि आम जन को इन नए प्रावधानों और नवाचारों के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिले।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा ई साक्ष्य एप का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पुलिस को घटनास्थल के वीडियो, फोटो और गवाहों के बयान डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने की सुविधा मिली है।

स्वच्छ व नियोजित कार्यस्थल से कार्यक्षमता में होती है बढ़ोतरी : रविकांत

जयपुर। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को सचिवालय के खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम अनुभाग में स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। प्रमुख सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने अभियान का नेतृत्व में सफाई अभियान के दौरान पत्रावलियों को सुनियोजित करने, काम म नहीं आ रही पत्रावलियों की बीड आउट कार्रवाई शुरु करने और साफ सफाई की गई। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने इस अवसर पर कार्मिकों से कहा कि कार्यस्थल पर साफ-सफाई हमारी नियमित आदत बननी चाहिए। इसके साथ ही पत्रावलियों का सही ढंग से संधारण, कार्यालय में उपयोग में आने वाली सामग्री, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कापियर, मेज-कुर्सी आदि की नियमित साफ-सफाई रखने और कार्यस्थल पर अनावश्यक वस्तुएं कचरा पात्र में ड़ालने, थूकने-पीक आदि से कार्यस्थल को गंदा नहीं करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित इस अभियान के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

प्रदेश में अवैध मदिरा पर कार्यवाही - हजारों लीटर वॉश एवं भट्टियां नष्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर,। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही कर अभियोग दर्ज किए गए। आबकारी आयुक्त नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के ग्राम मोरस व कोजरा में आबकारी निरोधक दल की दबिश कार्रवाई में 2500 लीटर वॉश, 2 पुरानी व एक चालू भट्टी को नष्ट किया। मौके से 9 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद कर नियमानुसार अभियोग दर्ज किया गया।

इसी प्रकार डूंगरपुर के आबकारी सर्कल सागवाड़ा में कडाना बैक वाटर क्षेत्र में स्थित ग्राम मेडी टेंबा में दबिश की कार्रवाई करते हुए 3 हजार लीटर वॉश नष्ट किया साथ ही 9 लीटर हथकड़ शराब जब्त कर अभियोग दर्ज किया। राजसमंद जिले के कामली घाट क्षेत्र में 400 लीटर वॉश एवं एक भट्टी को नष्ट किया।

मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में मंगलवार को चहल-पहल रही, क्योंकि पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण करने के अगले दिन वर्तमान और पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों और विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

'किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने मंगलवार को गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से राज्य में मत्स्य और डेयरी क्षेत्र को आधुनिक एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की।

इन दोनों परियोजनाओं...बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट... का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, किसानों की आय बढ़ाना और तकनीक आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। माना जा रहा है कि इनके क्रियान्वयन से राज्य

में मत्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र का तेज विकास होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार 'विकसित बिहार' के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और आने वाले समय में राज्य डेयरी, मत्स्य एवं पशुपालन के क्षेत्र में और अधिक प्रगति करेगा। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इन क्षेत्रों में और अधिक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बिहार सरकार के सात निश्चय3 कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश, 8,000 को मिलेगा रोजगार : बिजेंद्र प्रसाद यादव

पटना/भाषा। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) ने मेसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में करीब 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच के कारण ऊर्जा विभाग बिहार के लोगों और उद्योगों को निर्बाध एवं स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। यादव ने निवेशकों से बिहार में सर्वे कर अपनी उपयोगिता और औद्योगिक आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकासशील माहौल में बिहार सरकार ऊर्जा संरक्षण और रोजगार सृजन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बीएनपी ने अपार्टमेंट निवासियों के मुद्दों पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की

बेंगलूरु। बेंगलूरु नवनिर्माण पार्टी (बीएनपी) ने सोमवार को अपार्टमेंट निवासियों द्वारा हाल ही में प्रदर्शित सार्वजनिक असंतोष पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में पढ़े गए एक पत्र में उजागर की गई यह असंतोष की भावना, कई वर्षों से अपार्टमेंट निवासियों द्वारा सामना किए जा रहे मूलभूत मुद्दों की सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा का प्रत्यक्ष और अनुमानित परिणाम है। बेंगलूरु अपार्टमेंट्स फेडरेशन (बीएएफ) के संस्थापक और महासचिव श्रीकांत नरसिम्हन, जो इन मुद्दों के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत हैं, ने कहा, जब लंबे समय तक अनुरोध करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता, तो नागरिकों के पास अपनी निराशा व्यक्त करने के अलावा और क्या विकल्प बचता है। बीएनपी पिछले तीन वर्षों से अपार्टमेंट निवासियों की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार या उपमुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

'आप महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे फिर भी देशभक्त, हम विरोध करें तो देशद्रोही' : तृणमूल सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ''आप लोकतंत्र खत्म करेंगे, महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे फिर भी आप देशभक्त हैं और हम लोग विरोध करेंगे तो देशद्रोही हैं।'' उन्होंने सदन में 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में विधेयकों को पारित करने की बात ''अहंकार के साथ कही और यह भी कहा कि आप लोग (विपक्ष) चर्चा करो लेकिन हम लोग विधेयक पारित करके रहेंगे।''

तृणमूल सांसद ने कहा कि सरकार ''लोकतंत्र खत्म करे फिर भी देशभक्त है, महात्मा गांधी का नाम हटा दे फिर भी देशभक्त है। हम लोग विरोध करेंगे तो हम लोग देशभक्त नहीं हैं, देशद्रोही हैं।'' सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य इसी संदर्भ में सरकार पर निशाना साध रही थीं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए रखे जाने के बाद, रीजीजू ने कहा था, ''हमने पूर्व में परमाणु ऊर्जा विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन फिर विपक्षी दलों की ओर से अनुरोध किया गया कि विधेयक का अध्ययन करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए हमने सहमति जताई कि परमाणु विधेयक को हम कल लेंगे और आज हम बीमा विधेयक ले सकते हैं। यह सबके लिए अच्छा है किसी के लिए प्रतिकूल स्थिति नहीं है।''

रीजीजू ने कहा कि आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन ने भी सहमति जताई कि जरूरतमंद लोगों के हित में बीमा विधेयक को पहले लिया जाए और इसे यथाशीघ्र पारित करना चाहिए। शताब्दी रॉय ने बीमा विधेयक के संबंध में कहा कि सरकार को विधेयक पारित करने से पहले बीमा कंपनियों को मौका देना चाहिए और बीमा एजेंट का पक्ष जानना चाहिए।

बिरला ने सदस्यों से कहा: सदन 'ध्यान लगाने' का स्थान नहीं है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में कुछ सदस्यों से चुटकी लेते हुए कहा कि सदन ''ध्यान लगाने'' का स्थान नहीं है और यदि वे अपने घर से ही ''ध्यान लगाकर'' आएंगे तो उचित रहेगा। उन्होंने सदन में आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाने के बाद यह टिप्पणी की।

बिरला ने कहा, ''कई माननीय सदस्य यहीं पर ध्यान लगा लेते हैं। मेरा आग्रह है कि यहां ध्यान लगाने का स्थान नहीं हैं। ध्यान घर पर लगाकर आएं तो ठीक रहेगा।'' उनकी यह टिप्पणी सदन में कुछ सदस्यों के झपकी लेने की ओर इशारा करने वाली समझी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कई सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर रोजाना कार्यस्थगन का नोटिस दिए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस तत्काल विचार वाली और गंभीर समस्या के लिए दिया जाता है। बिरला का कहना था, ''देख रहा हूं कि कई सदस्य इसलिए नोटिस देते हैं कि मैं उनका नाम पढ़ूं। अगर वे रोज नोटिस लगाएंगे तो मैं उनका नाम पढ़ना बंद कर दूंगा।''

विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य व खुशनुमा जीवन से ही रचनात्मक समाज का निर्माण संभव : सर्वे

'क्यूएस-आई गेज' के 'इंस्टीट्यूशन ऑफ़ हैप्पीनेस' के सर्वे में खुलासा

नई दिल्ली। विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य व खुशनुमा जीवन(वेल बीइंग' एक स्वस्थ और रचनात्मक समाज के ज़रूरी हिस्से के तौर पर सामने आ रहे हैं, इसलिए एजुकेशनल संस्थान इन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे है। यह पहल भारतीय शिक्षा क्षेत्र की बदलती ज़रूरतों को दर्शाता है। भारतीय शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्रसिद्ध स्वतंत्र शिक्षण मूल्यांकन सिस्टम 'क्यूएस-आई गेज' ने अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस(आईओएच) प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया है जिसमें विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में विद्यार्थियों व शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य व खुशनुमा जीवन का आंकलन किया गया। इस बड़े सर्वे में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लगभग 5.5 लाख प्रतिभागियों(विद्यार्थी, शिक्षक, पूर्व विद्यार्थी और अभिभावक) से संपर्क किया गया। इस सर्वे का मकसद विद्यार्थियों व शिक्षकों के संतुष्टि स्तर को समझना और ऐसे तरीकों और नवाचार व पहल की पहचान करना था जो भावनात्मक मज़बूती, खुशी और सवार्गिण स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देते हैं।

पहले यूसीआई 2.2 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा भारत

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय साइकिलिंग के इतिहास में पहली बार उपमहाद्वीपीय पुरुष टीम एलीट रोड रेस पहले यूसीआई 2.2 बजाज पुणे ग्रां टूर 2026 का आयोजन पुणे में 19 से 23 जनवरी तक होगा।

इस टूर से अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग कैलेंडर का आगाज होगा । बजाज पुणे ग्रां टूर चार दिन तक चलने वाली चार चरण की 437 किलोमीटर की उपमहाद्वीपीय पुरुष टीम रोड रेस है । इसमें 26 देशों के 150 से अधिक पेशेवर अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट के भाग लेने की उम्मीद है । इसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार, पुणे जिला प्रशासन और भारतीय साइकिलिंग महासंघ कर रहे हैं ।

यहां टूर्नामेंट की ट्रॉफी के अनावरण के मौके पर खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने कहा ,'' 1960 से 1990 तक साइकिल भारत में आवागमन का जरिया था लेकिन 2000 के बाद से फिटनेस के प्रति जागरूकता बढने के बाद साइकिलिंग को दबाव में हमने अपनाया । '' उन्होंने कहा ,'' साइकिलिंग सबसे उत्तम व्यायाम है और यही वजह है कि फिट इंडिया का अहम हिस्सा है ।''

सरकार एसआईआर का इस्तेमाल अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कर रही : डेरेक ओ ब्रायन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का इस्तेमाल अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने तथा लोगों को बांटने के लिए कर रही है।

चुनाव सुधारों पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए ओ'ब्रायन ने कहा कि शाह ने केंद्र सरकार की नीति के रूप में डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट (पहचान करना, हटाना, निर्वासित करना) को जारी रखने की बात कही थी लेकिन उनका जोर डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड डिफ्लेक्ट (बांटने, भटकाने और ध्यान हटाने) पर है। उन्होंने सरकार पर लोगों को बांटने और धर्म एवं भाषा के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। ओ'ब्रायन ने कहा, आप कुछ अन्य राज्यों में बांग्ला बोलते हैं, तो आपको बांग्लादेशी बताकर निशाना बनाया जाता है। यही विभाजन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस महीने की शुरुआत में मानवीय आधार पर गर्भवती महिला और उसके आठ वर्षीय बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दिए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आप (सरकार) अवैध रूप से निर्वासित करते हैं, लेकिन कभी-कभी गर्भवती महिला को वापस लाया जाता है...। कुछ महीने पहले महिला को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया था। ओ'ब्रायन ने कहा, अपनी ही विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए, आप बहुत सारी दूसरी तरह की भटकाने वाली चीजें लेकर आते हैं और (उन विफलताओं से) ध्यान हटाते हैं। घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, बात घुसपैठियों की है सीमा का प्रभारी कौन है? मुख्यमंत्री नहीं, देश के गृहमंत्री हैं।

शासन को फैसले लेते समय न्याय, निष्पक्षता और नैतिकता को नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के एक सांसद ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार या शासन को फैसले लेते समय न्याय, निष्पक्षता और नैतिकता को नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई कानूनों को निरस्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' पर चर्चा के दौरान यह बात कही जिसे बाद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

कांग्रेस सांसद गोवाल कागदा पडवी ने 'निरसन और संशोधन विधेयक 2025' पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कानून का निरसन आसान है, लेकिन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना कठिन (हार्ड), जबकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना सर्वाधिक कठिन (हार्डेस्ट) होता है।

पडवी ने कहा कि प्रत्येक निरसन और संशोधन का संवैधानिक परिणाम और सामाजिक प्रभाव होता है, ऐसे में वह सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कानून अब क्यों निरस्त किये जा रहे हैं और इससे किसे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी चीजों पर विचार करके कानून का निरसन करना चाहिए न कि अपने फायदे के लिए।

कांग्रेस सांसद ने कहा, ''सरकार या शासन को फैसले लेते समय न्याय, निष्पक्षता और नैतिकता को नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए।'' उन्होंने भारतीय उत्तराधिकार कानून की धारा 213 से 'प्रोबेट' शब्द को हटाने के प्रावधान को मुसलमानों के विरुद्ध अन्य धर्म के लोगों के तुष्टीकरण का प्रयास करार दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर सरकार आदिवासियों से संबंधित वन अधिकार संशोधन कानून कब लाएगी।

मेस्सी के कार्यक्रम में अराजकता: डीजीपी और अन्य को कारण बताओ नोटिस, पुलिस उपायुक्त निलंबित

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को पिछले सप्ताह साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कथित कुप्रबंधन को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्य सचिव मनोज पंत के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिधाननगर के पुलिस उपायुक्त अनीश सरकार को भी निलंबित कर दिया है। साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम में 13 दिसंबर को हुए आयोजन के दौरान कथित कुप्रबंधन की जांच के लिए गठित जांच समिति की सिफारिशों के बाद यह कार्रवाई की गई। बयान में कहा गया है कि डीजीपी राजीव कुमार को जारी कारण बताओ नोटिस में कार्यक्रम स्थल पर सामने आयी खामियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब देने के लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। बिधाननगर पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार को भी इसी तरह का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे उस कार्यक्रम के प्रबंधन में आयुक्त कार्यालय की भूमिका एवं आचरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया, जिसके फलस्वरूप शनिवार को स्टेडियम परिसर के भीतर दर्शकों द्वारा बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ की गयी थी।

इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने ग्रीन, पथिराना पर जमकर किया खर्च

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अबूधाबी/भाषा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हरफनमौला ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के लिए रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए।

इस नीलामी में 'अनकैप्ड' (अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले) भारतीय खिलाड़ियों को भी बड़ी सफलता मिली। इसमें उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर और आक्रामक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक समान 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। दोनों खिलाड़ी 30 लाख रुपए की आधार मूल्य में आने के बाद आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे अधिक कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।

जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार को भी दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। दार की शुरुआती कीमत भी 30 लाख रुपए थी।

पृथ्वी साव और सरफराज खान जैसे भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी लय में होने के बावजूद इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। ग्रीन ने अपने हमवतन मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़ रुपए) को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया।

सीएसके ने युवा प्रशांत, कार्तिक पर लगाया बड़ा दांव

केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उनके लिए कड़ी बोली लगी, जिसके अंत में चेन्नई की फ्रेंचाइजी पिछड़ गयी। केकेआर ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु ने इस हरफनमौला को सात करोड़ रुपए की बोली के साथ अपनी से जोड़ा।

तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया। दो करोड़ रुपए की आधार मूल्य के साथ इस नीलामी में शामिल होने वाले पथिराना आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी के नियमों के अनुसार हालांकि शेष राशि बीसीसीआई के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में जाएगी। ऐसे में इस सत्र के लिए उनका वेतन 18 करोड़ रुपए (19 लाख अमेरिकी डॉलर) ही रहेगा। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पथिराना को हालांकि पूरी रकम मिलेगी क्योंकि वह वेतन सीमा के अंदर है।

केकेआर के प्रबंध निदेशक वेंकी मैसूर ने कहा कि फ्रेंचाइजी ग्रीन को जिस कीमत पर हासिल किया गया है, उससे वे खुश हैं। उम्मीद है कि ग्रीन आगामी सत्र में टीम को काफी मजबूती प्रदान करेंगे। मैसूर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम बहुत खुश हैं। इस पर हमारा ध्यान केंद्रित था और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। जिस कीमत पर हमने उन्हें खरीदा है, उससे हम संतुष्ट हैं। कीमत अगर इससे ज्यादा होती तो चिंता की बात होती। हम उन्हें खरीदने के इच्छुक थे और उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन अगर इससे नीलामी की हमारी योजना प्रभावित होती तो हम उन्हें जाने देते।'' उन्होंने आगे कहा, ''वे हमारी टीम को काफी मजबूती प्रदान करेंगे और हम जानते हैं कि वे बल्ले और गेंद से क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत खुश हैं।'' उन्होंने कहा, ''बीसीआई द्वारा 18 करोड़ रुपए के नियम पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि हमें कोई चिंता नहीं है, वैसे भी यह फ्रेंचाइजी को तो यह रकम देनी ही पड़ेगी।''

ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 29 मैचों में 707 रन बनाने के अलावा 16 विकेट भी चटकाए है। ग्रीन ने कहा, ''इस साल के आईपीएल के लिए कोलकाता का हिस्सा बनकर मैं बहुत उत्साहित हूं। ईडन गार्डन्स में जाकर वहां के माहौल से परिचित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे उम्मीद है कि यह साल हमारे लिए शानदार रहेगा। जल्द ही मिलते हैं। आमी केकेआर।'' बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को केकेआर ने सीएसके के साथ कई दौर की बोली के बाद 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा।

सूर्यकुमार अकेले पांचों मैच जिता सकते हैं : शिवम दुबे

लखनऊ/भाषा। हरफनमौला शिवम दुबे ने खराब फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव का बचाव करते हुए कहा कि भारत के टी20 कप्तान ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं और सही समय पर फॉर्म में लौटेंगे । सूर्यकुमार ने आखिरी टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था । विश्व कप में अब दो महीने से भी कम बाकी है लिहाजा उन पर दबाव बढता जा रहा है । दुबे ने कहा ,'' वह ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर पांचों मैच जिता सकता है । अगर वह फॉर्म में नहीं है तो इसके यह मायने नहीं है कि वह अच्छा खिलाड़ी नहीं है। वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से है । कोई और वह नहीं कर सकता जो उसने किया है । हां, अभी रन नहीं बन रहे हैं लेकिन सही समय पर वह फॉर्म में लौटेगा । किसी भी समय बड़ी पारी खेल सकता है ।'' दुबे ने कहा ,'' वह योद्धा है । वह रन बनाये या नहीं , वह ऐसे ही रहेगा । वह हमेशा टीम के लिये कुछ करना चाहता है । वह काफी आक्रामक खिलाड़ी है और 360 डिग्री बल्लेबाज है ।''

अभिज्ञान कुंडू, दीपेश देवेंद्रन ने भारत को मलेशिया पर 315 रन से जीत दिलाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/भाषा। अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड नाबाद 209 रन और दीपेश देवेंद्रन के पांच विकेट की मदद से भारत ने अंडर 19 एशिया कप मैच में मंगलवार को मलेशिया को 315 रन से हराया । यह रनों के अंतर से युवा वनडे में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है । इससे पहले 2022 में भारत ने युगांडा को 322 रन से हराया था ।

कुंडू युवा वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने । उन्होंने अपनी पारी में 125 गेंदों का सामना करके 17 चौके और नौ छक्के लगाये जिसकी मदद से भारत ने सात विकेट पर 408 रन जोड़े । जवाब में दाहिने हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज देवेंद्रन ने 22 रन देकर पांच विकेट चटकाते हुए मलेशियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी । मलेशिया की टीम 32.1 ओवर में 93 रन पर आउट हो गई । भारत के लिये वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद में 50 रन बनाये । उन्होंने यूएई के खिलाफ इसी टूर्नामेंट में 171 रन की पारी खेली थी । चौथे नंबर पर उतरे वेदांत त्रिवेदी और कुंडू ने चौथे विकेट के लिये 209 रन की साझेदारी की । कुंडू ने पारी में 55 सिंगल निकाले। सत्रह वर्ष के कुंडू दक्षिण अफ्रीका के जोरिच वान शाकविक के बाद युवा वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हो गए ।

जोरिच ने इस साल की शुरूआत में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 गेंद में 215 रन बनाये थे। त्रिवेदी ने 106 गेंद में सात चौकों की मदद से 90 रन बनाये । कुंडू ने कनिष्क चौहान के साथ पांचवें विकेट के लिये 87 रन की साझेदारी की ।

सुविचार

मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुःख इत्यादि के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'डंकी रूट' एजेंटों को कठोर संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डंकी रूट' से लोगों को अमेरिका भेजने वाले कई एजेंटों की करोड़ों रुपए की संपत्तियां कुर्क कर कठोर संदेश दिया है। ये लोग युवाओं को सुनहरे सपने दिखाकर उनसे लाखों रुपए लेते हैं और मुसीबतों में धकेल देते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो यह गंभीर समस्या बन गई है। वहां कई लोग अपने लड़कों को विदेश भेजने के लिए खेत, मकान और दुकान बेचने को तैयार हो जाते हैं। युवाओं में 'अमेरिका वाला लड़का' कहलाने का शौक बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका चले गए तो उनकी प्रतिष्ठा में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहां एक-दो साल टिककर कमा लिए तो शादी भी हो जाएगी। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। प्राय: अपने गांव में ईमानदारी से कमाने वाले युवाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता, जितना डंकी रूट से अमेरिका जाकर कमाने वालों को मिलता है। लोग अमेरिका का नाम सुनकर सोचते हैं कि वहां तो किसी चीज का अभाव नहीं है, आसमान से डॉलर ही डॉलर बरसते होंगे! उन्हें पता होना चाहिए कि असल अमेरिकी जीवन वह नहीं है, जो फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाया गया है। वहां भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर कमाई डॉलर में होती है तो खर्चे भी डॉलर में होते हैं। जो व्यक्ति अवैध तरीके से अमेरिका जाता है, उसे कदम-कदम पर शोषण का सामना करना पड़ता है। अगर सुरक्षा बलों की नजरों से बचने के बाद कहीं काम मिल गया तो कम वेतन मिलता है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले सकते। पकड़े जाने की तलवार हमेशा लटकी रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कई लोगों को जंजीरों से जकड़ कर स्वदेश भेज चुके हैं।

जिसके पास डंकी रूट वाले एजेंटों को देने के लिए चालीस-पचास लाख रुपए हैं, उसे कम-से-कम गरीब तो नहीं कहा जा सकता। अमेरिका जाने की ऐसी जिद एक छलावा है, जिसके शिकार भारतीय युवा हो रहे हैं। जब कोई एजेंट कहता है कि 'पक्का अमेरिका पहुंचा देंगे', 'पहुंचते ही नौकरी लगवा देंगे', 'एक साल में पूरा खर्चा वसूल हो जाएगा', तो युवाओं के मन में अमेरिकी जीवन की तस्वीरें तैरने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उस धरती पर कदम रखने की देर है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इन युवाओं को यह नहीं बताया जाता कि डंकी रूट पर कोई पुष्पवर्षा नहीं हो रही है! यह एक खतरनाक रास्ता है, जिसमें जंगल, रेगिस्तान, समुद्र को पार करना पड़ता है। रास्ते में बहुत उत्पीड़न होता है। कई लोग तो भूख, प्यास और मारपीट की वजह से जान गंवा देते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद नौकरी नहीं मिली तो रहने-खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है। भीख मांगने की नौबत आ जाती है। क्या लाखों रुपए किसी एजेंट को देकर इसलिए अमेरिका जाना है, ताकि वहां दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ फैलाएं? क्या इसमें कोई अक्लमंदी की बात है? ये लोग भारत में रहकर 10 हजार रुपए खर्च कर कोई काम नहीं सीखेंगे, क्योंकि उस समय यह रकम बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन लाखों रुपए किसी एजेंट को खुशी-खुशी थमा देंगे। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में सपनों के सौदागरों का लंबा-चौड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है। एजेंसियों को अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति भारतीय युवाओं को गुमराह कर उनसे धन लेता है और डंकी रूट से विदेश भेजता है, वह देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उसका अपराध क्षम्य नहीं है। जब एजेंसियां सख्ती बरतेंगी तो ऐसे तत्त्व युवाओं को गुमराह करने से परहेज करेंगे।

ट्वीटर टॉक

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को दिशा देने वाले पूज्य संत, पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज के देहावसान का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। समाज जागरण और धर्मसंरक्षण के लिए किया गया उनका तपस्वी पुरुषार्थ सदैव स्मरणीय रहेगा।

-दिया कुमारी

हमने बार-बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। सरकार इस केस को जबरन घसीट रही है। नेशनल हेराल्ड कंपनी से कोई पैसे निकाल नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई कुछ बेच नहीं सकता।

-प्रियंका गांधी वाड्रा

आप दवा कहीं और लगा रहे हो, लेकिन मर्ज कहीं और है। आपको अपना मर्ज ढूंढ़ना पड़ेगा। सिर्फ अपने कैडर को शांत करने के लिए यह गलत भ्रम फैलाना कि हम चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है।

-जेपी नड्डा

प्रेरक प्रसंग

स्वदेशी का गर्व

एक बार डॉ. कलाम ने तीन प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए हल्के कैलिपर का एक बेहतरीन तोहफा तैयार किया था, जो कार्बन सामग्री से निर्मित था। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, 'सर, आपने स्वदेश में हल्के कैलिपर का निर्माण करके पूरे विश्व के सामने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है।' दूसरा पत्रकार बोला, 'भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है और स्वदेश में ही अनेक तकनीकों का निर्माण कर सकता है।' तब कलाम अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराकर बोले, 'मैं तो स्वयं यह कहता हूं कि हमारे पास आश्चर्यजनक सफलताओं का पूरा इतिहास है। भारत प्रारंभ से ही विश्वगुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हमारा भारत हर चीज में अग्रणी है। गेहूं और चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। दूरसंचार उपग्रह के विकास में हम पहले स्थान पर हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास लाजवाब हैं। हमें हर स्वदेशी सफलता पर गर्व करना चाहिए।

सामयिक

युवा नेता नितिन नबीन बने कार्यकारी अध्यक्ष

भाजपा में युवा नेतृत्व की नई आहट पर भरोसा

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

भारतीय राजनीति में लंबे समय से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर युवा हाथों में सौंपने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यद्यपि यह नियुक्ति औपचारिक रूप से अस्थायी कही जा रही है, किंतु जिस प्रकार से इस निर्णय का पार्टी के भीतर और बाहर स्वागत हो रहा है, उससे यह संकेत स्पष्ट हैं कि भविष्य में उन्हें ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। यह नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की कार्यशैली, नेतृत्व-चयन और भविष्य-दृष्टि में आए एक बड़े परिवर्तन का उद्घोष है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक लिए गए साहसिक, अप्रत्याशित और दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णयों की श्रृंखला का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय भी है।

नितिन नबीन बिहार की राजनीति में कोई नया नाम नहीं हैं। वे पांच बार विधायक रह चुके हैं और जमीनी राजनीति की बारीकियों से भलीभांति परिचित हैं। संगठन और सरकार-दोनों के अनुभव से संपन्न नितिन नबीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके साथ ही संगठन के विभिन्न स्तरों पर उन्होंने जिस अनुशासन, रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है, वही उन्हें इस पद के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाता है। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और वैचारिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की क्षमता से परिपूर्ण है। यही गुण भाजपा की आत्मा भी है-जहां व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्थायी गुण रहा है-नए चेहरों पर भरोसा और पीढ़ीगत नेतृत्व का निर्माण। चाहे वह केंद्र सरकार में मंत्रियों का चयन हो, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो या संगठन में बदलाव-मोदी ने बार-बार यह साबित किया है कि वे भविष्य की राजनीति को आज गढ़ने में विश्वास रखते हैं। नितिन नबीन का चयन भी इसी विचारधारा का प्रतिफल है। यह निर्णय संकेत देता है कि भाजपा अब केवल चुनाव जीतने की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि अगले दो-तीन दशकों के लिए एक स्थायी वैचारिक और संगठनात्मक नेतृत्व तैयार कर रही है। युवा पीढ़ी, विशेषकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक संतुलन का केंद्र भी होता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति और समर्थन अनिवार्य माना जाता है। भाजपा की चुनावी सफलताओं में संघ की भूमिका सदैव निर्णायक रही है-चाहे वह विचार-प्रसार हो, कार्यकर्ता निर्माण हो या सामाजिक संपर्क। पिछले कुछ चुनावों में जिन परिस्थितियों का सामना पार्टी को करना पड़ा, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा संगठन और संघ के बीच पूर्ण सामंजस्य कितना आवश्यक है। ऐसे में नितिन नबीन का चयन यह संकेत देता है कि संघ और पार्टी नेतृत्व के बीच गहन विमर्श और सहमति के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यह नियुक्ति भाजपा को वैचारिक रूप से और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव हैं। यह राज्य लंबे समय से भाजपा के लिए रणनीतिक और वैचारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। यहां केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति, राष्ट्रवाद और सामाजिक संतुलन की भी परीक्षा होती है। एक संगठनात्मक अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की वास्तविक कसौटी यहीं होगी। यदि वे बंगाल में संगठन को नई धार देने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में सफल होते हैं, तो उनका नेतृत्व स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा। यही वह मंच है, जहां उनका रुतबा, कौशल और रणनीतिक दृष्टि राष्ट्रीय राजनीति के सामने स्पष्ट होगी।

भाजपा की राजनीति में एक विशेष परंपरा रही है-जहां कयास कुछ और होते हैं और निर्णय बिल्कुल अलग दिशा से आता है। अनेक नाम चर्चा में रहते हैं, अनेक चेहरे मंजिल के निकट आकर भी ठहर जाते हैं, किंतु अंतिम निर्णय अक्सर सबको चौंकाने वाला होता है। यही भाजपा की चमत्कार करने वाली' संगठनात्मक शैली है। नितिन नबीन का मनोनयन भी इसी परंपरा का हिस्सा है। यह निर्णय उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की क्षमता रखता है, जो लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रही थीं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भाजपा में पद नहीं, क्षमता निर्णायक होती है।

नितिन नबीन भारतीय राजनीति की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने संगठनात्मक निष्ठा, वैचारिक स्पष्टता और सतत जनसंपर्क को अपनी राजनीतिक पहचान बनाया है। छात्र राजनीति से लेकर सक्रिय सार्वजनिक जीवन तक उनका सफ़र अनुशासन, कर्मठता, राष्ट्रीयता और संघर्ष की पाठशाला रहा है। वे जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने वाले, जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझने वाले और उन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक मंचों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। नितिन नबीन की कार्यशैली में युवाओं के प्रति विश्वास, विकासोन्मुख सोच और पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पद को नहीं, दायित्व को प्राथमिकता देते हैं और संगठन के मूल्यों के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं।

नितिन नबीन सिन्हा कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। अभी उन्हें जेपी नड्डा की जगह पर भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जो अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री है। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतर से हार गईं। वे पटना जिले के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधान सभा के सदस्य हैं। 2 मार्च 2017 को, नबीन ने बिहार कांग्रेस के नेता अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया। मस्तान ने कथित तौर पर एक रैली में भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जूतों से मारने के लिए कहा था।

भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सशक्त संगठनात्मक आंदोलन है, जिसकी आत्मा उसका अनुशासित, समर्पित और वैचारिक रूप से सजग कार्यकर्ता है। पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहभागिता, संवाद और सामूहिक निर्णय की परंपरा को मजबूत करता है। संगठन नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अटूट विश्वास, स्पष्ट दिशा और नेतृत्व की पारदर्शिता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कार्यकर्ता स्वयं को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी मानता है। यही कारण है कि भाजपा में नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच विश्वास, प्रतिबद्धता और परस्पर सम्मान का संबंध दिखाई देता है, जो पार्टी को निरंतर सशक्त और गतिशील बनाए रखता है।

नितिन नबीन का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनयन केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं, बल्कि भाजपा के भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत है। यह युवा नेतृत्व, वैचारिक प्रतिबद्धता, संगठनात्मक अनुशासन और संघ-समन्वय का संगम है। यदि नितिन नबीन इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हैं-विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसी कठिन राजनीतिक भूमि पर-तो वे न केवल भाजपा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति में युवा नेतृत्व की नई परिभाषा भी गढ़ेंगे। यही वह क्षण है, जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि दृष्टि, धैर्य और दूरदर्शिता का प्रमाण बन जाती है।

भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सशक्त संगठनात्मक आंदोलन है, जिसकी आत्मा उसका अनुशासित, समर्पित और वैचारिक रूप से सजग कार्यकर्ता है। पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहभागिता, संवाद और सामूहिक निर्णय की परंपरा को मजबूत करता है। संगठन नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अटूट विश्वास, स्पष्ट दिशा और नेतृत्व की पारदर्शिता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।

नजरिया

मनरेगा के बाद ग्रामीण रोजगार की नई रूपरेखा

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

ग्रामीण भारत के विकास की यात्रा में मनरेगा एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा है। वर्ष 2005 में जब यह कानून अस्तित्व में आया था, तब देश के ग्रामीण समाज की जरूरतें, चुनौतियां और संरचना आज से बिल्कुल अलग थीं। उस समय व्यापक गरीबी, सीमित आजीविका के साधन और सामाजिक सुरक्षा के अभाव ने सरकार को एक ऐसे अधिकार-आधारित कानून की ओर प्रेरित किया, जो ग्रामीण नागरिक को काम का वैधानिक भरोसा दे सके। दो दशक बाद सरकार अब मनरेगा की जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या 'विकसित भारत जी राम जी' नाम से नए कानून को लाने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव केवल योजना का नहीं, बल्कि सोच और नीति के ढांचे का भी संकेत देता है।

सरकार का दावा है कि नया कानून मनरेगा की कमजोरियों को दूर करेगा और ग्रामीण भारत को अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के प्रति सक्षम बनाएगा। 100 दिनों की जगह 125 दिनों की रोजगार गारंटी, साप्ताहिक भुगतान, डिजिटल निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नियंत्रण और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे प्रावधान निस्संदेह आकर्षक लगते हैं। जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, आजीविका आधारित अवसंरचना और बाजार से जुड़ाव जैसे क्षेत्रों पर जोर यह दर्शाता है कि सरकार अब ग्रामीण रोजगार को केवल राहत के उपाय के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की रणनीति के रूप में देख रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना संग्रह में परिसंपत्तियों का पंजीकरण इस सोच को और स्पष्ट करता है कि गांवों में होने वाला हर कार्य राष्ट्रीय विकास की बड़ी तस्वीर से जुड़ा हो।

यह भी सच है कि पिछले वर्षों में ग्रामीण भारत में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। गरीबी दर में गिरावट, डिजिटल भुगतान की व्यापकता, आधार से जुड़ी सेवाएं और ग्रामीण आजीविका के नए अवसरों ने मनरेगा के मूल स्वरूप को कुछ हद तक अप्रासंगिक बना दिया है। मनरेगा के अंतर्गत दुरुपयोग, कागजों पर बने काम, मशीनों का अनुचित इस्तेमाल और फर्जी उपस्थिति जैसी शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार का यह कहना कि एक अधिक अनुशासित, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी ढांचे की जरूरत है, पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

फिर भी, इस नए कानून को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसके मूल दर्शन से जुड़ा है। मनरेगा की आत्मा यह थी कि काम मांगने पर काम देना राज्य का कानूनी दायित्व है। यह अधिकार गरीब ग्रामीण नागरिक को प्रशासन के सामने खड़ा होने का नैतिक और कानूनी बल देता था। नए कानून में मांग आधारित व्यवस्था की जगह मानक वित्तपोषण को अपनाने की बात कही गई है, जिसमें राज्यों के लिए बजट की एक तय सीमा होगी। भले ही सरकार यह आश्वासन दे कि रोजगार का अधिकार सुरक्षित रहेगा और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन व्यवहार में यह व्यवस्था अधिकार की धार को कुछ कुंद करती दिखाई देती है।

जब संसाधन पहले से सीमित होंगे, तो काम मांगने की स्वतंत्रता स्वतः ही सीमित हो सकती है। कृषि मौसम में 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों को रोकने का प्रावधान भी दोहरे अर्थ रखता है। एक ओर यह किसानों के हित में बताया जा रहा है, ताकि बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी न हो और कृषि लागत न बढ़े। दूसरी ओर, यह प्रावधान प्रशासनिक विवेक पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है। यदि किसी क्षेत्र में खेती के मौसम के बावजूद बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है, तो मजदूर के पास काम मांगने का विकल्प सीमित हो जाएगा। बिना स्पष्ट दिशा-निर्देश और अपील की व्यवस्था के यह प्रावधान नियंत्रण का औजार भी बन सकता है।

राज्यों पर वित्तीय बोझ का प्रश्न भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का वित्तीय अनुपात अपेक्षाकृत सक्षम राज्यों के लिए भले ही व्यावहारिक हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि राज्य अपने हिस्से का भुगतान समय पर नहीं कर पाते, तो रोजगार और मजदूरी दोनों प्रभावित होंगी। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी और गरीब नागरिक को अपने अधिकार के लिए किस दरवाजे पर जाना होगा।

पारदर्शिता और निगरानी के लिए प्रस्तावित तकनीकी उपाय-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीपीएस आधारित निगरानी और वास्तविक समय में जानकारी देने वाले डैशबोर्ड-सैद्धांतिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन तकनीक अपने आप में समाधान नहीं होती। यदि ग्राम पंचायतें केवल आंकड़े भरने वाली इकाइयों में बदल जाती हैं और ग्राम सभा की भूमिका कमजोर पड़ती है, तो स्थानीय स्वायत्तता का मूल विचार प्रभावित होगा। ग्रामीण विकास की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय समुदाय को योजना बनाने और निगरानी में कितनी वास्तविक भागीदारी मिलती है।

इस पूरे विमर्श में राजनीतिक और वैचारिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। मनरेगा के नाम से जुड़ा सामाजिक न्याय और अधिकार आधारित राजनीति का प्रतीकात्मक अर्थ रहा है। उसका हटना केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि नीति की दिशा में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने और व्यापक चर्चा की मांग कर रहा है, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से असंगत नहीं कहा जा सकता।

अंततः विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन को न तो पूरी तरह आशंका के चश्मे से देखा जाना चाहिए और न ही बिना शर्त उम्मीदों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा नीतिगत प्रयोग है जिसमें संभावनाएं भी हैं और जोखिम भी। यदि इसे सहमति, पारदर्शिता, संघीय संतुलन और स्थानीय क्षमता निर्माण के साथ लागू किया गया, तो यह सचमुच ग्रामीण भारत को टिकाऊ विकास की राह पर ले जा सकता है। लेकिन यदि अधिकार की भावना कमजोर पड़ी और क्रियान्वयन में राज्यों व पंचायतों की भूमिका सीमित हुई, तो यह सुधार के नाम पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच के क्षरण का कारण भी बन सकता है। विकसित भारत की नींव मजबूत तभी होगी, जब विकास के साथ अधिकार और विश्वास भी समान रूप से मजबूत रहें।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

रूस के युद्ध समाप्त करने के लिए शांति प्रस्ताव को कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा : जेलेंस्की

कीव/एपी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ पिछले चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अमेरिकी दूत अगले सप्ताहांत अमेरिका में संभावित बैठकों से पहले समझौते के मसौदे को रूस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।जेलेंस्की ने सोमवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि बर्लिन में दिन में अमेरिका के साथ चर्चा की गई शांति योजना का मसौदा बहुत ही व्यावहारिक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हालांकि आगाह किया कि रूस के कब्जे में उसके क्षेत्र सहित कुछ मुद्दे हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में की जा रही शांति की कोशिशें आगे बढ़ती प्रतीत हो रही हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका, यूक्रेन और पश्चिमी यूरोप के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति जता सकते हैं, जिनमें यूक्रेन के लिए युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी भी शामिल है।

अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उनके द्वारा तैयार की गई शांति योजना के लगभग 90 प्रतिशत बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोप में सहमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम शांति समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। हालांकि, अब भी कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन, देश के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण डोनबास क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर रूस के नियंत्रण को मान्यता नहीं देगा। डोनबास में लुहांस्क और दोनेत्स्क क्षेत्र शामिल हैं। रूस की सेना का इन दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। जेलेंस्की ने मंगलवार को नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा, अमेरिकी समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। वे डोनबास में एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव दे रहे हैं। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि 'मुक्त आर्थिक क्षेत्र' का अभिप्राय रूसी संघ के नियंत्रण में होना नहीं है।

अमेरिका ने साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को सराहा

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिकी नागरिकों से 85 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रयासों की सराहना करते हुए अमेरिका ने इसे दोनों देशों की साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने 'एक्स' पर पोस्ट एक संदेश में कहा, मजबूत कानून प्रवर्तन सहयोग के बदौलत, दोनों देश अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

दूतावास ने कहा, अमेरिका-भारत साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण। एफबीआई के समन्वय से, सीबीआई ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसने अमेरिकी नागरिकों से 85 लाख डॉलर की धोखाधड़ी की थी। सीबीआई ने नेटवर्क के सरगनाओं को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में अवैध धनराशि बरामद की। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई से मिली सूचनाओं के आधार पर, सीबीआई की टीम ने पिछले सप्ताह नोएडा में कार्रवाई शुरू की, जहां छह संदिग्धों को अमेरिकी नागरिकों से ठगी के आरोप में पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि टीम ने दिल्ली और कोलकाता में भी तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 1.88 करोड़ रुपए नकद, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क सहित 34 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अपराध से संबंधित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। वर्ष 2022 से 2025 तक, आरोपियों ने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, एफबीआई और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को धमकी दी कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर का इस्तेमाल धन शोधन और मादक पदार्थ की आपूर्ति के लिए किया गया है ।

घर से दूर प्रवासी मजदूरों की परायेपन और गुमनामी की कठोर हकीकतों को दर्शाती प्रदर्शनी 'अदरलैंड'

पणजी/भाषा

फोटोग्राफर समर जोधा ने यहां नेमिंग दोज़ कन्साइन टू नेमलेसनेस' नाम से बड़े-बड़े शहरों को चमकाने वाले गुमनाम प्रवासी श्रमिकों की कहानियों को अपनी तस्वीरों के माध्यम से बयां किया है। जोधा ने 10वें सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल में तस्वीरों के माध्यम से दुबई के बुर्ज खलीफा में काम करने वाले 3,500 से अधिक श्रमिकों की गुमनामी की भयावह कहानी को दर्शाया है। यह शो पहचान की अवधारणा की पड़ताल करते हुए उन लोगों के संघर्षों और सपनों को बयां करता है, जिन्हें समाज के हाशिये पर धकेल दिया गया है, जहां उनके नाम भी गुम हो जाते हैं। रंजीत होस्कोटे द्वारा संयोजित यह प्रदर्शनी 'अदरलैंड' में लगभग 1,200 श्रमिकों की तस्वीरें हैं, जिनमें से अधिकांश 'ग्लोबल साउथ' के थे। अदरलैंड, मातृभूमि की अवधारणा पर आधारित है, जो चार भारतीय फोटोग्राफरों – जोधा, नवीन किशोर, राम रहमान और रितेश उत्तमचंदानी – के कार्यों को एक साथ लाता है। ये तस्वीर अन्य समाजों में संकट, विकट परिस्थितियों, अशांति और उथल-पुथल के दौर के साक्षी रहे हैं। जोधा ने 'पीटीआई-भाषा'से बातचीत में कहा, मैं उन लोगों को देख रहा था, जो इसे (बुर्ज खलीफा) बना रहे थे, जिसका कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि हमारे अपने देश में भी इनका कोई महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी मानवीय गरिमा। उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में अपने तीन साल से अधिक की परियोजना के लिए लगभग 30 देशों के श्रमिकों से एक बोर्ड पर अपना नाम और अपनी पहचान बोर्ड पर लिखने को कहा और पासपोर्ट-शैली की तस्वीर खींची।

जोधा ने बताया ज्यादातर लोगों ने, बल्कि उनमें से कई लोगों ने, पासपोर्ट बनवाने से पहले कभी फोटो नहीं खिंचवाई थी। इसलिए हमने स्टूडियो में पासपोर्ट बनवाने का वही अनुभव दोबारा तैयार किया। वे हर सुबह आते थे। उनमें से कई लोगों को लिखना नहीं आता था। इसलिए उन्हें लिखना सीखना पड़ा, ताकि वे अपने पासपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकें। इस प्रक्रिया के अंत तक, जोधा के पास 3,500 से अधिक तस्वीरें थीं, जिनमें लोग अपने नाम, अंगूठे के निशान और निर्माण स्थल पर दिए गए नंबरों के माध्यम से अपनी पहचान बता रहे थे। इस सामूहिक प्रदर्शनी में फोटोग्राफ, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से बात कही गई है। इसे दमन की मशीनों के खिलाफ सामूहिक बेचैनी और एकजुटता के रूप, हाशिये पर गढ़े गए श्रम और आजीविका के रूप, प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने और कलाकार को एक गवाह और प्रतिभागी दोनों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो एक बाहरी व्यक्ति एक भीतर के व्यक्ति की भी भूमिका निभा रहा है।

मेसी से मिलकर गदगद हुए एल्विश और जन्नत

मुंबई/एजेन्सी

मशहूर फुटबॉल प्लेयर लियोनल मेसी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। हाल ही में मेसी से मशहूर कंटेंट क्रिएटर एल्विश यादव और टेलीविजन अभिनेत्री जन्नत ने मुलाकात की। दोनों ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। एल्विश यादव और जन्नत जुबैर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसी के साथ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में दोनों एक इवेंट में नजर आ रहे हैं। पोस्ट कर उन्होंने इसे कैप्शन दिया, हमने मेसी से मुलाकात की!! क्या शानदार दिन था। भारत में आपका स्वागत है। बहुत सारा प्यार। बता दें कि लियोनल मेसी अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं। विश्व कप विजेता खिलाड़ी की दीवानगी दुनियाभर में देखने को मिलती है। मेसी तीन दिन के भारत दौरे पर है, जिसका आज अंतिम दिन है। प्लेयर का ये दौरा शनिवार को कोलकाता से शुरू हुआ था और इस दिन ही शाम को वे हैदराबाद भी पहुंचे थे। रविवार को मेसी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की थी। सोमवार को दिल्ली में उनका आखिरी दौरा है, जहां पर वे कई लोगों से मुलाकात करेंगे।

लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर एल्विश यादव अपने फनी वीडियो, रोस्ट और व्लॉग्स के लिए जाने जाते हैं, और 2023 में बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता बनने के बाद इन्हें देशभर में पहचान मिली थी। वे एमटीवी रोडीज में गैंग लीडर भी रह चुके हैं और हाल ही में 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे शो में भी दिखे हैं। वहीं, अभिनेत्री जन्नत जुबैर ने 'फुलवा' और 'तू आशिकी' जैसे धारावाहिकों से प्रसिद्धि हासिल की थी और आज वे सोशल मीडिया पर भी लाखों दिलों की धड़कन हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद वह कई टीवी शोज और फिल्मों में भी नजर आई थीं, जिनमें 'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप', 'अलादीन', 'चांद के पार चलो', 'अंतरा', 'तू आशिकी', 'हार जीत', 'तुझसे नाराज नहीं जिंदगी', 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की', 'फुलवा', और 'काशी- अब न रहे तेरा कागज कोरा' जैसे टीवी सीरियल्स शामिल हैं।

फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई में मंगलवार को सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर लॉन्च किया गया। यह फिल्म मशहूर अभिनेता और सनी के पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पहली फिल्म है। इवेंट में फिल्म के बारे में बात करते हुए सनी देओल भावुक हो उठे। इवेंट में टीजर लॉन्च के दौरान सनी देओल ने अपनी फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग 'आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक' बोला। इस डायलॉग को बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें भावुक देख वहां मौजूद लोग एक पल के लिए शांत हो गए। इवेंट में सनी देओल ने देशभक्ति और युवा पीढ़ी के बारे में अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा, ''देश हमारी मां की तरह है और आज का युवा भी देश को उसी तरह प्यार करता है और उसकी रक्षा करना चाहता है, जैसे पहले की पीढ़ियां करती आई हैं। आज की युवा पीढ़ी में क्षमता है कि वह देश की परंपराओं को आगे बढ़ाए और उसे सुरक्षित रखे। चाहे इसे जेन-जी कहो या कुछ और, यह पीढ़ी भी अपने देश के लिए जिम्मेदार और संवेदनशील है।''

'बॉर्डर 2' फिल्म के टीजर लॉन्च में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और अन्य प्रमुख कलाकार भी मौजूद थे। इस दौरान अभिनेता अहान शेट्टी ने कहा, ''मैंने फिल्म के दौरान काफी कुछ सीखा है। सनी देओल, वरुण धवन, प्रोड्यूसर और निर्देशकों ने मेरी काफी मदद की है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं।'' 'बॉर्डर 2' 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है। पहले पार्ट में भी सनी देओल मुख्य किरदार में थे और इस बार भी वह लीड रोल में हैं।

इस फिल्म में मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह भी अहम किरदार में हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिन्होंने इससे पहले 'केसरी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बॉलीवुड में देशभक्ति और एक्शन का जादू फिर से पर्दे पर लौटने को तैयार है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर मंगलवार को आखिरकार रिलीज हो गया। यह टीजर दो मिनट चार सेकेंड का है। इसमें देशभक्ति की झलक को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। टीजर की शुरुआत सनी देओल की दमदार आवाज के साथ होती है। वे जोश और जुनून से भरी आवाज में कहते हैं, तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर कहेगा, 'हिम्मत है तो आगे आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान।' टीजर में भारत-पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं की झलक दिखाई गई है। शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई, यह सब टीजर में बेहद रोमांचक तरीके से पेश किया गया है। सनी देओल मिसाइल गन चलाते नजर आते हैं, वहीं वरुण धवन थल सेना के जवान के किरदार में दिखते हैं।

सोनू सूद ने बताई 'चैरिटी फाउंडेशन' शुरू करने की वजह

मुंबई/एजेन्सी

मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने अपने करियर में ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है, लेकिन असल जीवन में वे एक सच्चे हीरो से कम नहीं हैं। वे कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों की मदद से लेकर पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की सहायता करते नजर आए थे। अभिनेता ने सामाजिक कार्यों से समाजसेवा की एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन शुरू करने का उद्देश्य बताया। अभिनेता का कहना है कि फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत और यहां की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करवाना है। उन्होंने कहा, कई महिलाएं आर्थिक तंगी या सामाजिक कारणों से अस्पताल नहीं जा पातीं या फिर अपनी तकलीफें किसी से नहीं कह सकती हैं। हमारी इस पहल के तहत देश के किसी भी कोने में रहने वाली ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की सर्जरी पूरी तरह मुफ्त में करवाई जाएगी।

अभिनेता ने बताया कि उनकी टीम ने 500 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करवाई हैं, जिससे इतने ही लोगों की जान बची हैं और 500 से अधिक परिवारों को नया जीवन मिला है।

अभिनेता ने अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अपनी टीम और उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पीड़ित महिलाओं के मामलों की जानकारी दी और उन्हें फाउंडेशन तक पहुंचाया। उन्होंने आखिरी में कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मिले, तो उन्हें हमारे पास लाएं। हम उनका इलाज एकदम मुफ्त में करवाएंगे। एक नया जीवन देंगे और साथ में मिलकर इस देश को और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति दिलवाएंगे और एक नया अध्याय लिखेंगे कि किस तरह हम मिलजुलकर लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभिनेता अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्होंने साल 2020 में किसान की दो बेटियों की मदद की थी। दरअसल, सोशल मीडिया पर किसान की बेटियों का खेत जोतते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। सूद ने उस किसान परिवार को तुरंत एक ट्रैक्टर भिजवाया था।

पराग त्यागी ने दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को याद किया

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेता पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला को उनकी 43वीं जयंती पर याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। रीमिक्स संगीत 'कांटा लगा' पर अपनी शानदार प्रस्तुति से प्रसिद्धि पाने वालीं जरीवाला का 42 साल की उम्र में 27 जून को निधन हो गया था। त्यागी ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट साझा किया और कहा कि उनकी मां का जन्मदिन जरीवाला की जयंती के दिन ही पड़ता है।

इस पुराने वीडियो में अभिनेता की मां और जरीवाला एक साथ डांस करती नजर आ रही हैं। त्यागी ने कैप्शन में लिखा, लोग कहते हैं कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक महिला होती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास दो महिलाएं परी और मम्मी हैं, दोस्तों सोचो दोनों के जन्म की एक ही तारीख को है, 15 दिसंबर। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा। जरीवाला और त्यागी, पवित्र रिश्ता और जोधा अकबर जैसे दैनिक धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। दोनों 2010 में मिले थे और 2014 में शादी की थी। जरीवाला और त्यागी को लोकप्रिय रियलिटी शो नच बलिये में एक साथ देखा गया था।

मैं एक ही फिल्म दो बार भी नहीं देखती, लेकिन 'धुरंधर' 4-5 बार देखना चाहती हूं : एलनाज नौरोजी

मुंबई/एजेन्सी

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा देखने को मिल रहा है। 250 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी फिल्म को खूब तारीफ मिल रही है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई स्पाई-थ्रिलर दर्शकों के साथ ही सेलेब्रिटीज को भी खूब पसंद आ रही है। ईरानी मूल की अभिनेत्री और मॉडल एलनाज नौरोजी ने भी फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े। फिल्म की तारीफ के लिए एलनाज ने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज सेक्शन का सहारा लिया। 'धुरंधर' का पोस्टर पोस्ट करते हुए उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। एलनाज ने न केवल कहानी बल्कि निर्देशक और स्टारकास्ट को भी कमाल बताया। एलनाज ने पोस्ट में लिखा, मैं बस यही महसूस कर रही हूं कि वाह! क्या कमाल की फिल्म है। फिल्म मेकिंग अपने सबसे अच्छे रूप में है आदित्य धर। एक्टर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना ने बेजोड़ एक्टिंग की है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सिनेमा बहुत पसंद है, लेकिन आमतौर पर किसी भी फिल्म को वह दो बार से ज्यादा नहीं देखती हैं। लेकिन, 'धुरंधर' वह बार बार देखना चाहती हैं।

उन्होंने लिखा, मैं एक्टिंग के क्षेत्र से हूं और सिनेमा मुझे पसंद है। लेकिन मैं एक ही फिल्म को दो बार भी देखना पसंद नहीं करती। लेकिन, खास बात है कि 'धुरंधर' इतनी शानदार है कि इसे मैं तीन-चार-पांच या बार देखना चाहती हूं। 'धुरंधर' को दर्शकों के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारों से भी खूब तारीफ मिल रही है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की बहादुरी और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित फिल्म में रणवीर सिंह ने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई है, जबकि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी महत्वपूर्ण किरदार में हैं। फिल्म की कहानी कंधार हाइजैक, 26 नवंबर जैसी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। तारीफ के साथ ही फिल्म की आलोचनाएं भी हो रही हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे 'प्रोपेगेंडा' कहा है। एलनाज नौरोजी 'सेक्रेड गेम्स', 'मस्ती 4' के साथ ही बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं।

नए साल में पुरानी फिल्मों का दबदबा, 2016 की फ्लॉप फिल्म रही सुपरहिट

मुंबई/एजेन्सी

साल 2025 बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के लिए शानदार रहा। नई फिल्में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पुरानी क्लासिक्स और कल्ट फिल्मों की री-रिलीज ने सिनेमाघरों को गुलजार रखा। दर्शकों का पुरानी फिल्मों से भावनात्मक लगाव इतना गहरा निकला कि कई ऐसी फिल्में, जो पहली रिलीज पर फ्लॉप हो गई थीं, इस बार सुपरहिट रहीं। नॉस्टैल्जिया वेव की सफलता बताती है कि दर्शक बड़े पर्दे पर यादें फिर से जीना चाहते हैं। सनम तेरी कसम :- साल की सबसे बड़ी सफलता रही हर्षवर्धन राणे और मावरा होकाने की 'सनम तेरी कसम'। साल 2016 में रिलीज हुई यह ट्रैजिक रोमांटिक ड्रामा उस समय फ्लॉप हो गई थी। बॉक्स ऑफिस पर महज 9 करोड़ के आसपास कमाकर दम तोड़ने वाली फिल्म इस साल वैलेंटाइन वीक में री-रिलीज हुई और कमाल दिखाया। ओपनिंग डे पर 4.50 करोड़ की कमाई और टोटल कलेक्शन 40 करोड़ के पार पहुंची। अधूरी प्रेम कहानी, इमोशनल सीन्स और ट्रैजिक लव स्टोरी दर्शकों को थिएटर खींच लाई।

ये जवानी है दीवानी:- नए साल की शुरुआत में 3 जनवरी को रणबीर कपूर-दीपिका पादुकोण की 'ये जवानी है दीवानी' थिएटर में फिर से लौटी। दोस्ती, प्यार, ट्रैवल और सपनों की यह रोम-कॉम मूवी दर्शकों को खूब पसंद आई। री-रिलीज में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। खास बात है कि फिल्म की कहानी के साथ ही 'बदतमीज दिल' और 'कबीरा' जैसे गाने भी दर्शकों को उतने ही फ्रेश लगे, जितनी कहानी।

अंदाज अपना अपना :- कल्ट कॉमेडी 'अंदाज अपना अपना' एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए थिएटर में उतरी। आमिर खान-सलमान खान स्टारर साल 1994 की यह फिल्म पहली बार फ्लॉप थी। 4के वर्जन में री-रिलीज हुई तो दर्शकों का खासा प्यार मिला।

नमस्ते लंदन:- होली के मौके पर इस साल विपुल अमृतलाल शाह निर्देशित 'नमस्ते लंदन' भी फिर से रिलीज हुई। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, ऋषि कपूर, क्लाइव स्टैंडन और जावेद शेख स्टारर यह फिल्म भारतीय कल्चर, परिवार और प्यार की यादें ताजा कर गई। एनआरआई दर्शकों ने भी फिल्म को खूब पसंद किया।

रंगीला :- इस साल रिलीज हुई फिल्मों की लिस्ट में उर्मिला मातोंडकर, जैकी श्रॉफ और आमिर खान स्टारर रंगीला का भी नाम शामिल है। 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला।

शोले :- हीमैन धर्मेंद्र के निधन (24 नवंबर) के बाद उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म 'शोले' सिनेमाघरों में फिर से रीलीज हुई। 12 दिसंबर को रिलीज हुई 'शोले: द फाइनल कट' 4के रिस्टोर्ड वर्जन में आई। दर्शकों ने खचाखच भरे थिएटरों में फिल्म देखी। वीरू बनकर धर्मेंद्र की जोड़ी जय (अमिताभ बच्चन) के साथ अमर हो गई। 1 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज यह फिल्म धर्मेंद्र के लिए ट्रिब्यूट थी। इन फिल्मों के अलावा, 'घूमर', रजनीकांत स्टारर 'पदयप्पा' की सुपरस्टारडम, रेखा की 'उमराव जान' की क्लासिक अदाकारी, 'धड़कन' की इमोशनल लव ट्रायंगल, 'जो जीता वही सिकंदर' की यूथ एनर्जी, और 'बाहुबली' की एपिक स्केल ने दर्शकों को बांधे रखा। आयुष्मान खुराना-यामी गौतम की 'विक्की डोनर' ने स्पर्म डोनेशन जैसे टैबू पर हंसाया-रुलाया। राधिका आप्टे की 'हंटर', आलिया भट्ट-रणदीप हुड्डा की 'हाईवे' की खास जर्नी, संजय लीला भंसाली की 'पद्मावत', करिश्मा-सलमान की 'बीवी नंबर-1' ने भी अच्छी भीड़ खींची। वहीं, रोमांस लवर्स के लिए 'कहो ना प्यार है' ने ऋतिक की डेब्यू मैजिक याद दिलाई, 'कल हो ना हो' ने शाहरुख की इमोशनल जर्नी, 'लैला मजनू' ने इंटेंस लव स्टोरी, 'रॉकस्टार' ने रणबीर की म्यूजिकल सोल जर्नी, और 'रहना है तेरे दिल में' ने स्वीट रोमांस को सिनेमाघरों में फिर से दिखाया।

क्राइम और ड्रामा में अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने गैंगस्टर सागा की रॉ एनर्जी, 'तुम्बाड' ने हॉरर-फैंटसी की मास्टरपीस वाइब, 'सत्या' ने मनोज बाजपेयी की अंडरवर्ल्ड क्लासिक, और 'करण अर्जुन' ने शाहरुख-सलमान स्टारर फिल्म का धमाल दिखाया।

अट्ठम के तपस्वियों के हुए पारणे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां केएलपी अभिनंदन अपार्टमेंट के श्री संकल्प जैन संघ में पोष दशमी प्रभु श्री पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के अवसर पर पंच दिवसीय महामहोत्सव के अंतिम दिन करीब 108 अट्ठम के तपस्वियों का पारना हुआ। आचार्यश्री कुलबोधि सूरीश्वरजी म.सा., पंन्यासश्री ज्ञान बोधि विजयजी म.सा. एवं साध्वीश्री सौम्यरत्नाश्रीजी म.सा. की निश्रा कार्यक्रम में प्राप्त हुई।

केएलपी में स्थित कल्प हाउस में अट्ठम के तपस्वियों के पारणे के संपूर्ण लाभ मातु मधुदेवी जुगराज, मुकेशकुमार, जितेशकुमार, अमितकुमार, जैनमकुमार मेहता परिवार मरुधर में देसूरी ने लिया। श्री संकल्प जैन श्वेताम्बर संघ केएलपी ने लाभार्थी परिवार का सम्मान किया।

इस अवसर पर ट्रस्ट के सचिव मनीष परमार, ट्रस्टी भवरलाल परमार, कैलाश कोठारी व जितेश मेहता आदि उपस्थित थे।

राजाजीनगर में निःशुल्क एक्यूपंक्चर एवं एक्यूप्रेशर उपचार शिविर आयोजित

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। तेरापंथ युवक परिषद राजाजीनगर द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर एवं डे केयर श्रीरामपुरम के अंतर्गत आचार्यश्री तुलसी के संयम शताब्दी के अवसर पर निःशुल्क पंच दिवसीय मेगा एक्यूपंक्चर एवं एक्यूप्रेशर उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 60 सदस्य लाभान्वित हुए। सभी सदस्यों को एटीडीसी एवं डे केयर हॉस्पिटल द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं से अवगत करवाया गया। शिविर में एक्युपंक्चर एवं एक्युप्रेशर थेरापिस्ट अमित कपूर एवं शीतल बोहरा ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के प्रायोजक हंसराज अशोक, रवि, अजिंक्या चौधरी परिवार थे। तेयुप के अनेक सदस्यों ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मानव सेवा

बेंगलूरु की अमर्ट ग्लोबल शाखा के सदस्यों ने गत तीन दिनों में होयसलानगर, आरआर नगर एवं कमगोंडनहल्ली स्थित झुग्गी बस्तियों में शीतकालीन मानव सेवा के अंतर्गत 250 कम्बल वितरण किए। ग्लोबल बेंगलूरु के स्वयंसेवकों द्वारा कंबल वितरण कार्य से करीब 175 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए। इस बस्ती के बच्चों को ड्राइंग की किताबें, कलर पेंसिल, चॉकलेट इत्यादि भी बांटें गए।

स्वदेशी उपयोग का सभी संकल्प लें : कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां चेन्नई एसएस जैन संघ मंडल में राष्ट्रसंत श्री कमलमुनिजी कमलेश ने अपने प्रवचन में मंगलवार को कहा कि हमारे निर्दोष पर जुल्म करने वाले, उनका खून बहाने वाले, स्वाभिमान को कुचलने वाले का यदि हमारा ही व्यक्ति अभिनंदन करें ऐसे बढ़कर शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जिन अंग्रेजो ने माता की गोद सुनी की, बहनों का सुहाग छीना जुल्म किया उनके प्रतीक '31 दिसंबर' को मानना शहीदों के जख्म पर नमक छिड़कने के समान है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 1 जनवरी पर पागलपन का भूत सवार होता है। संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं।

उन्हें इस दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मनाना चाहिए जो हमारे सिर पर कलंक के समान है। गुलामी के प्रतीक को दूर करने का काम सरकार कर रही है। दुर्भाग्य हम उसको अपना रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी में जहर घोल रहे हैं। जैन संत ने कहा कि शहीदों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी और हम उनको शान से अपनाते हैं। अपने भाइयों को बेरोजगार करके उनके पेट पर लात मारकर कसाई जैसा काम करते हैं। हमें संकल्प लेना है स्वदेशी अपनाना है। भारतीय संस्कृति का नव वर्ष गुड़ी पड़वा है, जो विज्ञान और आध्यात्म से परिपूर्ण हैं।

उसको हर्षोल्लास के साथ मना कर लोगों में स्वाभिमान जागृत करेंगे। दिलीप नाबरिया, मुकेश सुराणा, रतन धारीवाल, राजेश आच्छा ने संतों का अभिनंदन किया।

मैथिल परिवार की कार्यकारिणी की बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में मिथिलांचल क्षेत्र के प्रवासित लोगों के लिए काम कर रहे मैथिल परिवार के सदस्यों एवं अधिकारियों ने गुमडीपुंडी के निजी आवास पर बिहार एवं मिथिला के लोगों के बेहतरी के लिए बैठक की। जिसमें दो दर्जन से भी अधिक अधिकारियों एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में मिथिलांचल एवं बिहार के लोगों के खोजबीन एवं उनके जीवन यापन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चाएं की गई। साथ ही आगामी 8 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन तय की गई।

संस्था के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि होली मिलन समारोह डीजी वैष्णव कॉलेज सभागार में 8 मार्च को अपराह्न 3:00 बजे से शुरू की जाएगी। जिसमें मिथिला के मशहूर मैथिली गायक विकास झा एवं रचना झा को आमंत्रित किया गया है। मैथिल परिवार के संस्थापक सदस्य पंकज झा एवं सचिव साकेत झा के अनुसार सैकड़ों की संख्या में मिथिला के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ मिथिला के लोगों के मौलिक समस्याओं से भी संस्था से जुड़े लोग रू-ब-रू होंगे।

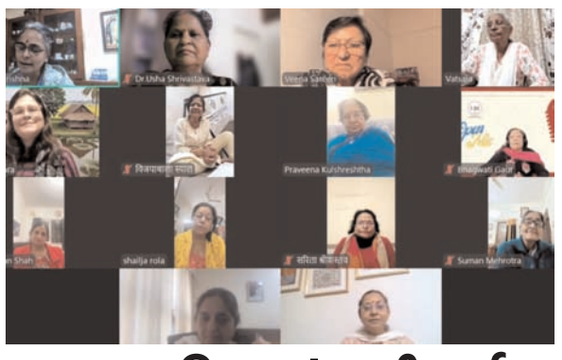

भाषा साहित्य मंच की वर्षांत गोष्ठी सोल्लास सम्पन्न

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के भाषा साहित्य मंच की वर्षांत ऑनलाइन मासिक गोष्ठी आयोजित की गई जो इस बार विषय एवं विधा मुक्त रखी गई थी। गोष्ठी में भारत के विभिन्न प्रदेशों से ही नहीं बल्कि सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया से भी रचनाकार जुड़े। मंच की वरिष्ठ सदस्या डॉ. वत्सला किरण ने दीप प्रज्वलन किया और नंदिनी माथुर की स्वरचित सरस्वती वंदना से गोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष डॉ. उषा श्रीवास्तव ने स्वागत करते हुए मंच की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंच के सदस्यों द्वारा एकत्रित राशि का उपयोग कई संस्थाओं व देश के सैनिकों को आर्थिक एवं आवश्यक खेल सामग्री सहयोग आदि का वितरण करने में किया गया। तत्पश्चात विद्या कृष्णा, वीना सरीन, लता शाह, सरिता श्रीवास्तव, पूर्णिमा श्रीनिवासन, विजयाबाला स्याल, प्रवीणा कुलश्रेष्ठ, भगवती सक्सेना, सुदेश वत्स, डॉ. उषा श्रीवास्तव, डॉ.वत्सला किरण श्रीमती नंदिनी माथुर, रीना दयाल, त्रिशला मिश्रा तथा डॉ भूमिका श्रीवास्तव, डॉ सुमन मेहरोत्रा, डॉ शैलजा रोलाने आदि ने अपनी विविधतापूर्ण मनोरंजक रचनाओं की प्रस्तुति दी।

त्रिशला मिश्रा ने गोष्ठी का संचालन किया। प्रवीणा कुलश्रेष्ठ ने सभी को धन्यवाद दिया।

तिरुपरनकुंड्रम दीप प्रज्वलन प्रकरण में उच्च न्यायालय ने कहा :

स्तंभ को लेकर तीन संस्करण हैं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान उसके समक्ष तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के स्तंभ (दीपाथून) के संदर्भ में तीन अलग-अलग संस्करण प्रस्तुत किए गए हैं। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने एक दिसंबर को एक एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें तीन दिसंबर को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने मामले में पक्षकार बनने की मांग को लेकर अदालत कक्ष में एक वकील द्वारा हंगामा किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही, न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने के लिए कहे जाने के बावजूद इस वकील ने अदालत कक्ष के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया। वकील के व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए, उच्च न्यायालय ने सीआईएसएफ को उसे अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दिया। सीआईएसएफ कर्मियों के आने और उसे बाहर निकालने तक, वकील लगातार चिल्लाता रहा।

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के के रामकृष्णन की खंडपीठ ने अधिवक्ता अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई के लिए मामले को तमिलनाडु बार काउंसिल को भेज दिया। जब आज खंडपीठ ने एक दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई शुरू की, ''तो वकील अब्दुल मुबीन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा, दरगाह और उसके आसपास का इलाका हमारा है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए, यह (दीपाथून) हमारा है।'' इस पर न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा, ''अब स्तंभ के संदर्भ में तीन संस्करण हैं।'' वह स्पष्ट रूप से सरकारी अधिकारियों द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए इस दावे का जिक्र कर रहे थे कि प्राचीन दीपक स्तंभ एक 'सर्वेक्षण पत्थर' है और यह एक 'जैन संरचना' है। वर्ष 1920 के एक आदेश, जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह क्षेत्र दरगाह का हिस्सा था, का हवाला देते हुए मुबीन ने कहा, यह निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि नेल्लीथोपे से पहाड़ी की चोटी तक जाने वाली सीढ़ियां मस्जिद की हैं।'' उन्होंने कहा कि निष्कर्ष में कहा गया कि दरगाह और उसके आसपास की चीजें मुसलमानों की हैं। उन्होंने कहा,एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन) ने निष्कर्षों को नजरअंदाज कर दिया। एकल न्यायाधीश का कहना है कि पत्थर के दीपाथून तक पहुंचने के लिए चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है। मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं यह प्रस्तुत करूं कि वहां केवल दरगाह के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। मुबीन ने दावा किया कि 'दीपाथून' शब्द पहली बार गढ़ा गया है और अगर इसे इस नाम से पुकारा जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा,आखिरकार, हर धर्म की अपनी-अपनी मान्यताएं होती हैं।

इस पर न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा, ''सुविधा के लिए, आप इसे पत्थर का स्तंभ कह सकते हैं। मुबीन ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए पहाड़ी की तस्वीरें प्रस्तुत कीं और कहा कि 1920 के आदेश के अनुसार पहाड़ी पर स्थित मंडपम भी मुसलमानों का है और पहाड़ी तक दरगाह के माध्यम से ही पहुंचा सकता है। पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में एएसआई का रुख सुनना चाहती है कि बिना उसकी अधिसूचना के पहाड़ियों पर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हिंदू श्रद्धालुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीराम ने कहा कि यह पहला मामला है, जिसमें यह तर्क उठाया गया है कि एकल न्यायाधीश का आदेश संविधान की शपथ के विरुद्ध है। अदालत इस मामले में आगे की दलीलें कल सुनेगी।

यूईएफ व्यापार शिखर सम्मेलन का हुआ समापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। गिंडी स्थित चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित दो दिवसीय यूईएफ व्यापार शिखर सम्मेलन का शानदार समापन हुआ। समापन अवसर पर यूईएफ तथा यूएनएसडीसी (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास परिषद) के बीच उद्यमिता तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड रुपए के आंतरिक कोष का शुभारंभ किया गया।

इस आंतरिक कोष का उपयोग उद्यमिता स्टार्टअप्स एवं व्यवसाय के विस्तार हेतु किया जाएगा यह यूईएफ एवं बलमुरुगन आईएएस के नेतृत्व में अनिकेत कैपिटल का संयुक्त फंड है। यूईएफ एवं यूएनएसडीसी के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर यूईएफ के अध्यक्ष अहमद बुहारी तथा भारत के सतत विकास परिषद के अध्यक्ष अजमल दस्तगीर ने हस्ताक्षर किए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

करगा उत्सव

बेंगलूरु के श्री स्नेहा जीवी युवक संघ कुरुबरहल्ली द्वारा नगर देवता श्री अण्णम्मा देवी करगा उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं विद्यार्थियों में शिक्षण सामग्री वितरित की। आयोजकों ने मुणोत का सम्मान किया।

मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण इरादे उजागर हो गए हैं : सिद्दरामय्या ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा

बेंगलूरु। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर दिल्ली की अदालत द्वारा संज्ञान लेने से इनकार करने के कदम का स्वागत करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को कहा कि इससे नरेन्द्र मोदी सरकार के ''दुर्भावनापूर्ण इरादे'' पूरी तरह से उजागर हो गए हैं। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी कहा कि अब देश के सामने उजागर हो गया है कि मोदी सरकार सत्ता का ''दुरुपयोग'' कर रही है। उन्होंने कहा, ''सत्य और न्याय की जीत हुई है।''

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड' मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सिद्दरामय्या ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''माननीय न्यायालय ने मोदी सरकार की अवैध कार्यवाही और दुर्भावनापूर्ण इरादे को पूरी तरह उजागर कर दिया है। यंग इंडियन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही को क्षेत्राधिकार से बाहर और अवैध घोषित किया गया है।''

उन्होंने कहा, ''मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा हूं, जिन्होंने साहस और गरिमा के साथ इस प्रतिशोध का सामना किया है।

निर्माणाधीन सच्चियाय माता मंदिर में गूंजे माता के जयकारे व भजन

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के सच्चियाय माता जैन सेवा संघ के तत्वावधान में रविवार को सच्चियाय माता जैन सेवा मंडल द्वारा सदस्यों के लिए बिड़दी स्थित निर्माणाधीन सच्चियाय माता मंदिर परिसर में एक भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

संघ के अध्यक्ष मदन राज बोहरा ने स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थापक ट्रस्टी अरुण भंसाली ने ट्रस्ट की ओर से अब तक हुए मंदिर निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रस्तावित कम्युनिटी परिसर योजना से सभी सदस्यों को अवगत कराया। इस योजना हेतु मनोज बाफना परिवार एवं फुटरमल दाँतेवाड़िया परिवार द्वारा सहर्ष आर्थिक सहयोग की स्वीकृति प्रदान की गई।

सुख का खजाना धन, सत्ता व पदार्थों में नहीं अपितु सत्य आत्मा में है : साध्वीश्री भव्यगुणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के शाश्वत कुटुंब अपार्टमेंट में विराजित साध्वीश्री भव्यगुणाजी ने कहा कि आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण होकर सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो जाती है। दुःख का पहला कारण अपनी आकांक्षा है। दुःख कहीं बाहर से नहीं आता, वह अपनी आकांक्षा, कामना, इच्छा से आता है, वह अपनी लालसा से आता है, वह अपने मन से आता है, पहले किए हुए पाप के फल से भी आता है। उन्होंने कहा कि दुःख और सुख का उद्गम स्थल भी अपना मन है। जहाँ मन शान्त हुआ, वहीं सुख का अमृत स्रोत फूट पड़ता है। जहाँ इच्छाएँ, वासनाएँ मरी, वहीं आनन्द हिलोरें मारने लगता है। जहाँ आकांक्षा-तृष्णा का दहन हुआ, वहीं सुख का झरना फूट पड़ता है। सुख का खजाना धन, सत्ता व पदार्थों में नहीं, सत्य आत्मा में है। सच्चा परम सुख तो आत्मा में है।

साध्वी शीतलगुणाजी ने कहा कि जब तक 'मैं' का पता नहीं, तब तक 'मेरे' का भी पता नहीं। 'मैं' का ज्ञान ही मेरे' का बोध कराता है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तब उसे जीवन, संबंधों, कर्तव्यों, साधना और कर्म सबका स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। आत्मा का परिचय ही जीवन का प्रथम और मूल परिचय है। बिना आत्मबोध के सारी दौड़, सारे प्रयास और सारी उपलब्धियाँ अधूरी हैं। सुनील कुंकुलोल ने बताया कि साध्वीद्वय से सिमंधर स्वामी राजेंद्र सूरी गुरुमंदिर संघ मामुलपेट में आयोजित आगामी गुरुसप्तमी महोत्सव में शामिल होने के लिए मामुलपेट संघ के ट्रस्टी मेघराज भंसाली, हेमराज मोदी, तिलोकचंद भंडारी अपार्टमेन्ट पहुंचे और साध्वियों से निवेदन किया, जिसे साध्वीश्री ने स्वीकार किया। आगामी गुरु सप्तमी साध्वीवृंद की निश्रा में होगी।

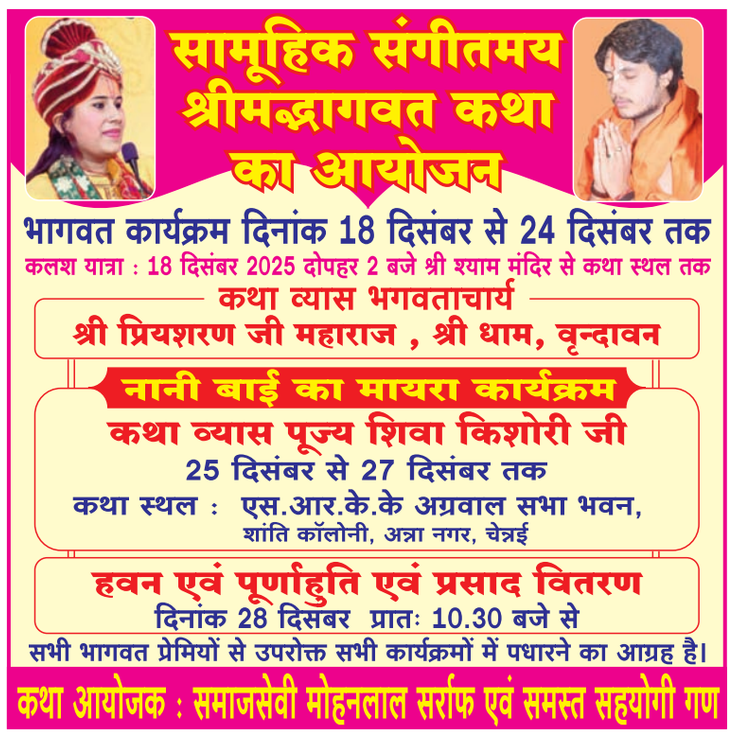

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Aditya at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.